संस्थापक : स्व. श्री वीर विक्रम आदित्य

हिन्द जनपथ

स्थापना वर्ष : 2002

पंचकूला
बुधवार
21 जनवरी, 2026
वर्ष:24 अंक: 209
कुल पृष्ठ:08
मूल्य : 1 रुपया

खबरें छापते हैं छुपाते नहीं | दैनिक प्रभात संस्करण हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश से एक साथ प्रकाशित। | www.hindjanpath.com

राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल पंचकूला में, मुख्यमंत्री गुरुग्राम में फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज

पेज-8

मान सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, गन्ने पर 68.50 रुपए प्रति क्विंटल सब्सिडी को मंजूरी

- पंजाब सरकार अब देश में गन्ने की सबसे अधिक कीमत दे रही है
- पंजाब कैबिनेट ने गन्ने पर सीधी सब्सिडी और एम.एस.पी. आधारित सहायता प्रदान कर किसानों को बड़ी राहत दी
- मुख्यमंत्री मान ने योगशाला के अंतर्गत 1,000 योग प्रशिक्षकों के पदों के सृजन को भी मंजूरी दी

हिन्द जनपथ
चंडीगढ़ (ब्यूरो)। यहां मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक विशेष रूप से किसान-कल्याण के लिए फैसले लेने पर केंद्रित रही, जिसमें कैबिनेट द्वारा निर्धारित स्टेट एग्रीड प्राइस में से 68.50 रुपए प्रति क्विंटल सीधी सब्सिडी की मंजूरी दी गई, जिससे पंजाब राज्य गन्ना किसानों को देश में गन्ने का सबसे अधिक भाव देने में लगातार अग्रणी चल रहा है।

यह फैसला मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में विभिन्न सुधारों के साथ लोगों की तंदुरुस्त स्वास्थ्य संबंधी पहलकदमियों और शहरी प्रशासन में विभिन्न सुधारात्मक कदम उठाने संबंधी मंजूरियां शामिल हैं, जो पंजाब सरकार की निर्णायक और परिणाम-आधारित पहुंच को दर्शाता है।

मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए मुख्य मंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि निजी चीनी मिलों की ओर से गन्ना किसानों को 2025-26 पिराई सीजन के लिए निर्धारित स्टेट एग्रीड प्राइज में से 68.50 रुपए प्रति क्विंटल सब्सिडी सीधे तौर पर अदा की जाएगी। उन्होंने बताया कि पंजाब पहले ही देश में गन्ने के लिए सबसे अधिक 416 रुपए प्रति क्विंटल स्टेट एग्रीड प्राइस दे रहा है, जो पिछले साल से 15 रुपए की वृद्धि दर्शाता है। यह पंजाब के गन्ना काश्तकारों को देश भर में सबसे अधिक भाव मिलना सुनिश्चित बनाने के साथ-साथ किसानों के लिए आय सुरक्षा को और मजबूत करेगा।

जन स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर निरंतर ध्यान केंद्रित करते हुए मंत्रिमंडल ने 'सीएम दी योगशाला' प्रोजेक्ट के अधीन योग ट्रेनरों की 1,000 अतिरिक्त पदों के सृजन को भी मंजूरी दे दी है। बैठक के दौरान यह भी बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान इस पहलकदमी के लिए 35 करोड़ का बजट प्रबंध किया जाएगा, जिसका उद्देश्य एक स्वस्थ और तंदुरुस्त पंजाब की सृजन को सुनिश्चित बनाना है।

स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को मजबूती देने के एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने मुक्तसर जिले के गांव बादल, तरन तारन जिले के खडूर साहिब, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जलालाबाद और फाजिल्का जिले के टर्शरी केयर सेंटर को बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (बीएफयूएचएस), फरीदकोट में पूरी तरह हस्तांतरित करने की मंजूरी भी दे दी है। इस हस्तांतरण से इन क्षेत्रों के निवासी यूनिवर्सिटी के उन्नत मेडिकल बुनियादी ढांचे और विशेषज्ञता का लाभ उठाकर बेहतर इलाज और जांच सेवाओं तक पहुंच कर सकेंगे।

मंत्रिमंडल ने पंजाब मैनेजमेंट एंड ट्रांसफर म्यूंसिपल एक्ट, 2020 की धारा 4 के अधीन निर्देशों के गठन और नोटिफिकेशन को भी मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य पंजाब सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों और जन क्षेत्र के अन्य संस्थानों से संबंधित म्यूंसिपल संपत्तियों को जन उद्देश्यों के लिए हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान करना है। ये फैसले राज्य भर में विकास परियोजनाओं को नई गति देने के साथ-साथ जमीन के वितरण में एकरूपता सुनिश्चित करने और सरकारी जमीन के दुरुपयोग को रोकने में विशेष रूप से सहायक होंगे। संबंधित जिले के डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व वाली एक कमेटी आवंटन प्रक्रिया की सिफारिश करेगी, जो राज्य सरकार की मंजूरी के अधीन होगी।

जमीन संसाधनों की सर्वोत्तम उपयोग के माध्यम से विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने म्यूंसिपल सीमाओं के अंदर सभी सरकारी-लाइसेंसशुदा परियोजनाओं के अधीन स्थित खाली छोड़े या उपयोग में आने वाले रास्तों या जल मार्गों (खालों) की बिक्री या एक्सचेंजों द्वारा हस्तांतरण के लिए भी नीति को मंजूरी दे दी। इस नीति का उद्देश्य विकास की संभावनाओं को तलाशना और शहरी योजना के परिणामों को बेहतर बनाना है।

मंत्रिमंडल ने पी.ए.पी.आर.ए. (पंजाब किफायती संपत्ति रजिस्ट्रेशन एक्ट) लाइसेंसशुदा परियोजनाओं के लिए समय अवधि 1 जनवरी, 2026 से 31 दिसंबर, 2026 तक एक साल बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी। यह वृद्धि प्रति एकड़ 25,000 रुपए की एक्सटेंशन फीस पर अधिकतम तीन सालों तक की अवधि के लिए दी जाएगी और संबंधित सक्षम अधिकारियों द्वारा पहले लागू नियमों और शर्तों के अनुसार इसकी अनुमति दी जाएगी।

शहरी विकास संबंधी एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने जनवरी 2026 के बाद नीलामी के लिए रखी जाने वाली प्रस्तावित संपत्तियों के लिए अतिरिक्त सतही क्षेत्र अनुपात के लिए खर्च निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले फॉर्मूले को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही 20 फरवरी, 2025 को नोटिफाई की गई ई-ऑक्शन नीति 2025 के पैरा 10.2 में संशोधनों को भी मंजूरी दे दी गई, जिससे भविष्य में विकास अधिकारियों द्वारा नीलाम की जाने वाली सभी श्रेणियों की संपत्तियों पर लागू संशोधित उपबंध बनाए गए।

मंत्रिमंडल ने नियम 6A शामिल कर पंजाब सिविल सर्विसेज (सेवा की सामान्य शर्तें) नियमों, 1994 में संशोधनों को भी मंजूरी दे दी।

संशोधन के अनुसार न्यूनतम शैक्षिक और अन्य योग्यताओं सहित योग्यता मापदंड निर्धारित करने की अंतिम तिथि आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि होगी, जब तक कि संबंधित सेवा नियमों में विशेष रूप से अन्य तिथि निर्धारित न की गई हो।

फसली विविधता को प्रोत्साहित करने के लिए एक अग्रगामी कदम के तहत मंत्रिमंडल ने पंजाब के बागवानी क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए जापानी तकनीक पेश करने के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ भागीदारी को भी मंजूरी दी। यह भागीदारी बागवानी विकास, कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे, पानी प्रबंधन और हुनर विकास पर केंद्रित होगी, जिसका उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था में बागवानी क्षेत्र के योगदान को दोगुना करना है।

मोटी-मोटी बातें

तंज़ानिया–हरियाणा के मध्य व्यापार एवं कृषि सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु उच्चस्तरीय बैठक आयोजित

हिन्द जनपथ
चंडीगढ़ (ब्यूरो)। तंज़ानिया और हरियाणा के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा विदेश सहयोग विभाग एवं नागरिक उड्डयन विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती अमनीत पी. कुमार की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। बैठक में व्यापारियों एवं प्रगतिशील किसानों के साथ तंजानिया में कृषि गतिविधियों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार (विदेश सहयोग विभाग) श्री पवन चौधरी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान तंज़ानिया में कृषि यंत्रों की संभावित मांग, विभिन्न क्षेत्रों के अनुरूप फसल चयन, बागवानी एवं दलहन फसलों की संभावनाएं, सिंचाई के लिए जल उपलब्धता तथा विद्युत आपूर्ति जैसे विषयों पर बिंदुवार चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त, खनन (माइनिंग) क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न मुद्दे एवं प्रश्न भी बैठक के समक्ष रखे गए।

श्रीमती अमनीत पी. कुमार ने व्यापारियों एवं किसानों द्वारा प्रस्तुत सभी सुझावों और प्रश्नों को गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि हरियाणा सरकार अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक संरचित, पारदर्शी और व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि व्यापारियों और किसानों को तंज़ानिया में निवेश एवं कृषि गतिविधियों से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियाँ समयबद्ध और सटीक रूप से उपलब्ध कराई जाएँ।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि तंज़ानिया में संभावनाओं के आकलन हेतु सर्वेक्षण, फील्ड स्टडी तथा अन्य आवश्यक कार्यों के लिए संबंधित विभागों एवं अधिकारियों की स्पष्ट जिम्मेदारियाँ निर्धारित की जाएँगी, ताकि आगे की कार्ययोजना को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा सके। इस दिशा में सरकारी स्तर पर समन्वय स्थापित कर व्यापारियों एवं किसानों को हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। बैठक के दौरान उपस्थित व्यापारियों ने हरियाणा सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पहल से न केवल व्यापारियों और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि हरियाणा और तंजानिया के बीच दीर्घकालिक, मजबूत और परस्पर लाभकारी साझेदारी को भी नई गति प्राप्त होगी।

सहारनपुर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों के शव मिले

सहारनपुर (उप्र)- सहारनपुर के सरसावा थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी से मंगलवार सुबह दंपति समेत परिवार के 5 शवों को पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि थाना सरसावा क्षेत्र की कौशिक विहार कॉलोनी में एक मकान के कमरे में अमीन के पद पर कार्यरत अशोक राठी (40), उसकी पत्नी अजिंता (37), मां विद्यावती (70), पुत्र कार्तिक (16) और देव (13) के शव बरामद हुए। अमीन के पास से तीन पिस्टल भी मिली हैं।

सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) आशीष तिवारी ने बताया कि आज सुबह ही पुलिस को यह जानकारी मिली कि सरसावा की कौशिक विहार कॉलोनी में एक अमीन सहित उनके परिवारजनों के कुल 5 शव उन्हीं के मकान के एक कमरे में मिले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। मृतकों के शव एक ही कमरे में पाए गए। अशोक राठी के शव के बगल में तीन लोडेड पिस्टलें भी मिलीं। अमीन के पद पर कार्यरत रहे अशोक राठी सहित सभी के सिर पर गोली लगी है।

गोली बहुत पास से मारी गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा अशोक राठी सहित उसके पारिवारिक परिवेश की जानकारी ली जा रही है और पूरे क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मौके से बरामद तीनों पिस्टल देशी हैं और वह लाइसेंसी हैं या नहीं, इसकी जांच कराई जा रही है। एसएसपी ने अब तक की छानबीन के हवाले से बताया कि अशोक राठी को अपने पिता की मौत के बाद उनकी जगह मृतक आश्रित श्रेणी में अमीन की नौकरी मिली थी। वह नकुड़ तहसील में अमीन के पद पर कार्यरत था।

उसके दोनों बेटे दसवीं और 11वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। पुलिस ने अमीन अशोक राठी के घर को सील कर दिया है, ताकि किसी भी स्तर पर जांच प्रभावित न हो पाए। एक ही परिवार के पांच सदस्यों के शव बरामद होने की सूचना मिलते ही सहारनपुर के डीआईजी अभिषेक सिंह, एसएसपी आशीष तिवारी, एसपी देहात सागर जैन सहित फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पांचों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।

तमिलनाडु विधानसभा में टकराव, राज्यपाल ने 'गलतियों' वाले अभिभाषण से किया इनकार, माइक बंद करने का आरोप

चेन्नईः तमिलनाडु विधानसभा में मंगलवार को अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो गई, जब राज्यपाल आर. एन. रवि ने सदन में अपने पारंपरिक अभिभाषण के दौरान राज्य सरकार द्वारा तैयार पाठ को पढ़ने से इनकार कर दिया। राज्यपाल का कहना था कि अभिभाषण में कई गंभीर 'गलतियां', असत्यापित दावे और भ्रामक तथ्य शामिल हैं। इस विवाद पर राजभवन ने तीखी प्रतिक्रिया जारी की है।

राजभवन ने आरोप लगाया कि विधानसभा में राज्यपाल का माइक बार बार बंद किया गया और उन्हें अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया। बिना अभिभाषण दिए 234 सदस्यीय विधानसभा से बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद राजभवन ने 13 बिंदुओं में विस्तार से बताया कि राज्यपाल ने संबोधन पढ़ने से इनकार क्यों किया।

राजभवन के अनुसार प्रस्तुत अभिभाषण में कई ऐसे दावे शामिल थे, जिनकी पुष्टि नहीं की जा सकती, जबकि आम जनता से जुड़े कई गंभीर और संवेदनशील मुद्दों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। बयान में कहा गया कि इस तरह का अभिभाषण संवैधानिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है।

निवेश के मुद्दे पर भी राजभवन ने राज्य सरकार के दावों पर सवाल उठाए। बयान में कहा गया कि तमिलनाडु में 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश आने का दावा वास्तविकता से कोसों दूर है। संभावित निवेशकों के साथ हुए समझौता ज्ञापन अधिकतर कागजों तक सीमित हैं और वास्तविक निवेश उसका बहुत छोटा हिस्सा है। राजभवन के मुताबिक चार साल पहले तक तमिलनाडु विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पाने वाले राज्यों में चौथे स्थान पर था, जबकि अब वह छठे स्थान पर बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा है।

राजभवन ने यह आरोप भी लगाया कि राष्ट्रगान का एक बार फिर अपमान किया गया, जो मूलभूत संवैधानिक कर्तव्य की अनदेखी है। बयान में यह भी कहा गया कि राज्य में दलितों के खिलाफ अत्याचार और दलित महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन अभिभाषण में इन मुद्दों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया। राज्यपाल और सत्तारूढ़ द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम सरकार के बीच यह टकराव एक बार फिर राज्य की राजनीति में केंद्र राज्य संबंधों, संवैधानिक भूमिका और जवाबदेही को लेकर नई बहस छेड़ता दिख रहा है।

नितिन नबीन को PM मोदी की बधाई, बोले- पार्टी से संबंधित मामलों में मेरे 'बॉस' हैं

नई दिल्ली- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को नितिन नबीन को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी और कहा कि पार्टी से संबंधित मामलों में यह युवा नेता उनका 'बॉस' होगा। यहां पार्टी मुख्यालय में एक सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने 45 वर्षीय नबीन को एक ''मिलेनियल'' बताया, जो उस पीढ़ी से ताल्लुक रखते हैं, जिसने भारत में बहुत सारे बदलाव देखे हैं।

नबीन को संगठन पर्व के समापन पर पार्टी मुख्यालय में भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया, जिसमें बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के विभिन्न पार्टी पदों के लिए चुनाव हुए। मोदी ने कहा कि जब बात पार्टी के विषयों की आती है, तब माननीय नितिन नबीन जी...मैं एक कार्यकर्ता हूं और आप मेरे बॉस हैं। अब माननीय नितिन नबीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं और उनका दायित्व सिर्फ भाजपा को संभालना ही नहीं है बल्कि राजग के सभी साथियों के बीच तालमेल का दायित्व भी उन्हें संभालना है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि नबीन उस युग से ताल्लुक रखते हैं, जिसमें लोग बचपन में रेडियो पर खबरें सुनते थे और अब कृत्रिम मेधा (एआई) का उपयोग करने में माहिर हैं। नितिन जी में युवा ऊर्जा और भरपूर अनुभव दोनों हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में भाजपा ने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है।

मोदी ने कहा कि इस सदी में एम. वेंकैया नायडू और नितिन गडकरी जैसे नेताओं के साथ-साथ हमारे कई वरिष्ठ सहयोगियों ने संगठन का विस्तार किया। राजनाथ जी के नेतृत्व में पहली बार भाजपा ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया। फिर अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा ने कई राज्यों में सरकारें बनाईं और केंद्र में लगातार दूसरी बार सत्ता में आई। जेपी नड्डा के नेतृत्व में भाजपा पंचायत से लेकर संसद तक हर स्तर पर मजबूत हुई।

हरियाणा भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा के कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण होने पर दीपक गर्ग ने दी शुभकामनाएं

हिन्द जनपथ
पंचकूला (ब्यूरो)। हरियाणा भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा उर्फ़ योगी के कार्यकाल के सफलतापूर्वक दो वर्ष पूर्ण होने पर दीपक गर्ग, भारतीय जनता युवा मोर्चा हरियाणा के प्रदेश मीडिया प्रभारी, ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। दीपक गर्ग ने कहा कि योगेंद्र शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा हरियाणा ने संगठनात्मक मजबूती, चुनावी सफलता और युवाओं को जोड़ने के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है।

दीपक गर्ग ने कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा उर्फ़ योगी के दो वर्ष का कार्यकाल युवाओं के विश्वास, समर्पण और संगठनात्मक क्षमता का प्रतीक रहा है। इस अवसर पर योगेंद्र शर्मा ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, मार्गदर्शक संघटन, संगठन की पूरी टीम तथा प्रदेश भर के युवा कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि योगेंद्र शर्मा के नेतृत्व में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के दौरान युवा मोर्चा की भूमिका ऐतिहासिक रही। इन चुनावों में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ता ने पूर्ण मनोयोग और निष्ठा के साथ कार्य किया, जिसके परिणामस्वरूप हरियाणा में तीसरी बार ऐतिहासिक रूप से भाजपा सरकार का गठन संभव हो सका। यह सफलता युवाओं की कड़ी मेहनत और संगठन की मजबूत रणनीति का परिणाम है।

दीपक गर्ग ने बताया कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान बूथ स्तर पर भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। मतदाता संपर्क, जनजागरूकता और संगठनात्मक समन्वय के माध्यम से युवा मोर्चा ने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान की। प्रत्येक बूथ पर युवा कार्यकर्ताओं की सक्रियता चुनावी जीत का मजबूत आधार बनी।

उन्होंने आगे कहा कि विधानसभा स्तर पर युवा सम्मेलनों का आयोजन कर युवाओं को संगठन से जोड़ने और उन्हें राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित किया गया।

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा चौथा वार्षिक धार्मिक समागम

हजूरी रागी भाई सरूप सिंह के जत्थे द्वारा शब्द गायन

हिन्द जनपथ
चंडीगढ़ (ब्यूरो)। पंजाब के सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा आज यहां पंजाब सिविल सचिवालय-1 के गुरुद्वारा साहिब में चौथा वार्षिक धार्मिक समागम आयोजित किया गया।

दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व को समर्पित नए साल की आमद के अवसर पर आयोजित इस समागम में श्री दरबार साहिब के हजूरी रागी भाई सरूप सिंह जी के जत्थे द्वारा रसमयी कीर्तन किया गया। इससे पहले श्री सुखमनी साहिब का पाठ किया गया। सरबत के भले के लिए अरदास की गई। इस अवसर पर गुरु का लंगर अटूट वितरित किया गया।

धार्मिक समागम में पंजाब के कैबिनेट मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, श्री अमन अरोड़ा, स. गुरमीत सिंह खुड्डियां तथा स. हरदीप सिंह मुंडियां, आप के जनरल सेक्रेटरी और मीडिया इंचार्ज श्री बलतेज सिंह पन्नू, लोक संपर्क विभाग के सचिव श्री रामवीर, आम राज प्रबंध के सचिव श्रीमती गौरी प्राशर जोशी, स्पेशल डीजीपी स. अमरदीप सिंह राय, मुख्यमंत्री के ओएसडी (मीडिया) श्री अमनजोत सिंह तथा डायरेक्टर मीडिया कम्युनिकेशन श्री अनिल सैनी, लोक संपर्क विभाग के डायरेक्टर डॉ. अक्षिता गुप्ता, अतिरिक्त डायरेक्टर श्री संदीप सिंह गढ़ा तथा डिप्टी सेक्रेटरी श्री दीपांकर गर्ग, आम राज प्रबंध के संयुक्त सचिव श्री तेजदीप सिंह सैनी, एडीओ-1 सुखविंदर सिंह, राज्य सूचना कमिश्नर हरप्रीत सिंह संधू और डॉ निर्मल जौरा ने विशेष रूप से उपस्थिति दर्ज की।

इस धार्मिक समागम में पंजाब सिविल सचिवालय-1, पंजाब सिविल सचिवालय-2, सी.आई.एस.एफ. तथा पंजाब विधान सभा के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित लोक संपर्क विभाग के मौजूदा तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों और मीडिया कर्मियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। विभाग के समूह स्टाफ द्वारा लंगर की सेवा स्वयं की गई।

दस्तारों का लंगर लगाया

पंजाब के सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा आयोजित धार्मिक समागम की विशेष बात यह रही कि इस अवसर पर दस्तारों का लंगर विशेष रूप से लगाया गया। विभाग के पूर्व कर्मचारी तथा प्रवासी पंजाबी आलीशान नरूला द्वारा विशेष रूप से दस्तारों की सेवा निभाई गई और धार्मिक समागम के दौरान समूह स्टाफ ने रंग-बिरंगी दस्तारें सजाकर सेवा की।

एनआईटी हमीरपुर एक सप्ताह में शुरु करेगा आईआईटी विस्तार परिसर भगोटला का सर्वे

मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार गोकुल बुटेल सहित आईआईटी मंडी के निदेशक ने किया भूमि का निरिक्षण

पालमपुर । पालमपुर के भगोटला में प्रस्तावित आईआईटी मंडी के विस्तार परिसर (एक्सटेंशन सेंटर) के निर्माण का सर्वे एक सप्ताह में शुरु कर दिया जाएगा। एनआईटी हमीरपुर की टीम इस सर्वे को अंजाम देगी। इस संबंध में आईआईटी मंडी की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मामले पर आज मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (नवाचार, डिजीटल तकनीक एवं गवर्नेंस) गोकुल बुटेल सहित आईआईटी मंडी के निदेशक प्रो. लक्ष्मीधर बेहरा और पालमपुर प्रशासन ने प्रस्तावित स्थल का दौरा किया। इस दौरान गोकुल बुटेल ने प्रशासन से विभिन्न मामलों पर फीडबैक लिया और उचित दिशा निर्देश भी जारी किए। दौरे के दौरान प्रो. लक्ष्मीधर बेहरा ने जानकारी दी कि एनआईटी हमीरपुर की टीम निर्माण कार्य के सर्वे को लेकर एक सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई शुरु कर देगी। गोकुल बुटेल ने इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रस्तावित निर्माण स्थल तक उचित सड़क सुविधा होनी चाहिए ताकि निर्माण सामग्री को निर्बाध निर्माण स्थल तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने वन स्वीकृति के मामलें पर भी फीडबैक लिया। प्रशासनिक अधिकारियों ने इस दौरान जानकारी दी कि करीब 20 हेक्टेयर भूमि की वन स्वीकृति मिल चुकी है और करीब 30 हेक्टेयर भूमि का मामला लंबित है। इस पर आवश्यक कार्रवाई जारी है। इस दौरान निर्माण को लेकर अन्य तकनीकि पहलुओं पर भी गौर किया गया। प्रो. लक्ष्मीधर बेहरा ने इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने भी मामले पर समन्वय स्थापित करने की बात कही। दौरे के दौरान उनके साथ एसडीएम पालमपुर नेत्रा मेती, अधिक्षण अभियंता लोक निर्माण बीएम ठाकुर, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विनीत शर्मा, जल शक्ति विभाग के अधिशाषी अभियंता पंकज ब्यास, डीएफओ संजीव शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

नीति आयोग के इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स में देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हिमाचल: मुकेश अग्निहोत्री

एम फिटनेस ऐप किया गया लॉन्च

शिमला। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज यहां राज्य परिवहन विकास एवं सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार परिवहन क्षेत्र में पारदर्शिता, डिजिटल सुधार, सड़क सुरक्षा, रोजगार सृजन और हरित मोबिलिटी को प्राथमिकता देकर निरंतर कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि जनवरी 2023 से दिसंबर 2025 की अवधि में परिवहन विभाग ने 2,597.59 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है, जो पिछली सरकार की समान अवधि की तुलना में 1,098 करोड़ रुपये (लगभग 73 प्रतिशत) अधिक है। यह वृद्धि सुदृढ़ प्रवर्तन व्यवस्था और डिजिटल पहलों का प्रत्यक्ष परिणाम है। उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग के इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स में हिमाचल प्रदेश का अग्रणी राज्यों में शामिल होना राज्य सरकार की हरित परिवहन और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार 'हरित हिमाचल' के संकल्प को पूरी दृढ़ता के साथ साकार करने के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी।

उन्होंने कहा कि वित्त विभाग की व्याख्यात्मक ज्ञापन वर्ष 2024-25 के आंकड़े अनुसार परिवहन विभाग राजस्व/कर अर्जित करने के मामले में राज्य कर एवं आबकारी विभाग के बाद प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि वाहन फिटनेस प्रणाली को वैज्ञानिक और पारदर्शी बनाने के लिए स्वचालित वाहन परीक्षण केंद्र (एटीएस) स्थापित किए जा रहे है। सरकारी क्षेत्र में ऊना के हरोली और हमीरपुर के नादौन में इन केंद्रो का निर्माण किया जाऐगा, जबकि निजी क्षेत्र में कांगड़ा के रानीताल, बिलासपुर, मंडी के कांगू, सोलन के नालागढ़, सिरमौर के पांवटा साहिब में स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से रानीताल एटीएस का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है व शेष में कार्य तीव्रगति से चल रहा है। इसके अतिरिक्त बद्दी में निरीक्षण एवं प्रमाणन केंद्र का 95 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसे शीघ्र चालू करने का लक्ष्य है।परिवहन मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा वाहन फिटनेस एवं अन्य परिवहन सेवाओं को डिजिटल, पारदर्शी और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए मोबाइल फिटनेस ऐप एवं ऑटो-अप्रूवल मैकेनिज्म लागू किए जाऐंगें। इसके तहत वाणिज्यिक वाहनों का डिजिटल फिटनेस परीक्षण फोटो एवं जीपीएस आधारित साक्ष्यों के साथ किया जाएगा तथा आवश्यक दस्तावेज पूर्ण होने पर परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं स्वतः स्वीकृत होंगी। उन्होंने कहा कि पेपरलेस कार्यप्रणाली से नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं सुनिश्चित होंगी और इससे नागरिकों को आरटीओ कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने बताया कि फरवरी 2025 से सोलन के बनलगी और हमीरपुर के नादौन में दो पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जहां अब तक 1,692 पुराने वाहनों को वैज्ञानिक तरीके से स्क्रैप किया जा चुका है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला है। इसके अतिरिक्त ड्राइविंग टेस्ट प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए जिला ऊना के हरोली में 10.23 करोड़ रुपये की लागत से स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक एवं ट्रैफिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य इस वर्ष पूर्ण होने की संभावना है।

उन्होंने कहा कि पुरानी पेट्रोल/डीज़ल टैक्सियों को ई-टैक्सी में परिवर्तित करने पर 40 प्रतिशत सब्सिडी तथा 390 नए बस रूटों पर बस खरीद के लिए 30 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। जिसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके अलावा, स्वरोजगार और हरित मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ई-टैक्सी योजना भी लागू की गई है। इसके तहत 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है और अब तक 96 लाभार्थियों को 6.94 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है। परिवहन मंत्री ने कहा कि विभाग मैनुअल प्रवर्तन से डिजिटल प्रवर्तन की ओर कदम बढ़ा रहा है जिसके तहत ई-चालान प्रणाली, ई-पहचान प्रणाली (ई-डिटेक्शन सिस्टम) और इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) लागू किए गए हैं, जिनके माध्यम से यातायात प्रवर्तन को फेसलेस एवं डिजिटल बनाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि छठी से बारहवीं कक्षा तक सड़क सुरक्षा पाठ्यक्रम लागू किया गया है तथा सभी हितधारक विभाग जैसे लोक निर्माण, पुलिस, शिक्षा एवं स्वास्थय विभाग को कुल 2057.34 लाख रुपये सड़क सुरक्षा गतिविधियों के तहत आवंटित किए गए है, जिसके सकारात्मक परिणामस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं में 10 प्रतिशत, मृत्यु दर में नौ प्रतिशत तथा गंभीर रूप से घायलों की संख्या में छह प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

परिवहन मंत्री ने कहा कि रोजगार सृजन के क्षेत्र में 1,061 स्टेज कैरिज बस रूट निजी क्षेत्र को स्वीकृत किए गए हैं तथा 39,000 से अधिक टैक्सी/मैक्सी परमिट जारी किए गए हैं, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।इस अवसर पर उन्होंने विभाग की एम फिटनेस ऐप का भी शुभारम्भ किया। यह ऐप डिजिटल फिटनेस निरीक्षण, फोटो और जीपीएस साक्ष्य, फर्जी प्रमाण-पत्रों की रोकथाम, कागज-रहित प्रक्रिया तथा रियल-टाइम डेटा समन्वयन को सुविधाजनक बनाता है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में परिवहन विभाग परिसर, शिमला में सौर ऊर्जा आधारित ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। राज्य में 129 स्थानों को ईवी चार्जिंग स्टेशन हेतु चिन्हित किया गया है, जिनमें से 30 स्टेशन वर्तमान में संचालित किए जा हैं। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. नज़ीम, हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक निपुण जिन्दल, परिवहन आयुक्त नीरज कुमार, आईजी ट्रैफिक गौरव सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

250 करोड़ से बनेगा मनाली रिवर फ्रंट: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने मनाली में विंटर कार्निवल-2026 का किया शुभारंभ

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज पर्यटन नगरी मनाली में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले विंटर कार्निवल-2026 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 300 झांकियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा माल रोड पहुंचने पर इन झांकियों का अवलोकन भी किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मनाली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 250 करोड़ रुपये की लागत से रिवर फ्रंट विकसित करने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने परिधि गृह मनाली के नए भवन में अतिरिक्त पांच कमरे बनाने, मनाली क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा के लिए आवश्यक सात चिन्हित स्थानों के लिए सुरक्षा दीवार लगाने, ओल्ड मनाली में दो करोड़ की लागत से पार्किंग निर्माण तथा गांव सोलंग तथा कराल में भूस्खलन के न्यूनीकरण संबंधी कार्यों के लिए 25-25 लाख रुपये प्रदान करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुन्दरता, सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक धरोहरों और अतिथि-सत्कार परम्परा के कारण देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करता है। प्रदेश में प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में पर्यटक आते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के अनुभवों को यादगार बनाने के उद्देश्य से प्रमुख पर्यटन स्थलों पर विंटर कार्निवल जैसे भव्य आयोजनों को निरंतर प्रोत्साहित कर रही है।

ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार है। राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश को प्राकृतिक, धार्मिक, साहसिक, आध्यात्मिक तथा स्वास्थ्य पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस दिशा में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 'ग्रीन हिमाचल बॉयोडायवर्सिटी पार्क' तथा नदियों के किनारे पार्क विकसित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नई इको-टूरिज्म नीति लागू की गई है, जिसके अंतर्गत नवंबर, 2025 तक 11 इको-टूरिज्म साइटों का आवंटन किया जा चुका है तथा 27 अन्य साइट्स की आवंटन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इससे पर्यटन के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रैकिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 245 ट्रैकिंग रूट चिन्हित किए गए हैं तथा पर्यटकों की सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप भी विकसित की जा रही है। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से प्रदेश में रोप-वे परियोजनाओं को भी गति प्रदान की जा रही है।

ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि होम-स्टे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन किए गए हैं तथा होम-स्टे इकाइयों के लिए ब्याज अनुदान योजना आरंभ की गई है। होम-स्टे स्थापित करने या मौजूदा होम-स्टे के विस्तार एवं उन्नयन हेतु अधिकतम पांच करोड़ रुपये के निवेश पर शहरी क्षेत्रों में तीन प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में चार प्रतिशत तथा जनजातीय क्षेत्रों में पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया जा रहा है। होम-स्टे पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी आरंभ किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी जिला मुख्यालयों को वर्षभर हवाई संपर्क से जोड़ने के लिए हेलीपोर्ट निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश में कुल 16 नए हेलीपोर्ट विकसित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में हमीरपुर के जसकोट, कांगड़ा के रक्कड़, पालमपुर, चंबा के सुल्तानपुर, कुल्लू के आलू ग्राउंड और मनाली, किन्नौर के शाबो तथा लाहौल-स्पीति के जिस्पा, सिस्सू और रंगरिक में नौ हेलीपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं, जबकि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार की प्रक्रिया भी प्रगति पर है।

उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला को हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया गया है। देहरा उप-मंडल के बनखंडी में लगभग 619 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विश्व-स्तरीय वन्य प्राणी उद्यान का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त शिमला जिला के कुफरी स्थित हसन घाटी में प्रदेश का पहला स्काईवॉक ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बागवानी पर्यटन की संभावनाओं को भी तलाशा जा रहा है।

लखनऊ में आयोजित पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में बोले कुलदीप पठानियां, पारदर्शिता लोकतंत्र की आत्मा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा विधान भवन मंडप लखनऊ में आयोजित 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां ने कहा कि पारदर्शिता लोकतंत्र की आत्मा है। जब नागरिकों को यह ज्ञात होता है कि कानून कैसे बनते हैं, किस आधार पर निर्णय लिए जाते हैं और उनके प्रतिनिधि संसद में क्या भूमिका निभा रहे हैं, तब लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास मजबूत होता है। प्रौद्योगिकी इस पारदर्शिता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से संसद/ सदन की कार्यवाही लाईव प्रसारण विधेयकों का ऑनलाईन प्रकाशन, सांसदो की उपस्थिती और मतदान रिकॉर्ड की सार्वजनिक उतलब्धता नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से विधायी प्रक्रिया से जोड़ती है। भारत में संसद टी0वी0 लोक सभा और राज्य सभा की वेबसाइटें तथा मोबाईल ऐप्स इस दिशा में उल्लेखनीय कदम हैं।

हिमाचल के संदर्भ में बोलते हुए पठानियां ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पेपर लेस एसैम्बली होने वाला पहला राज्य है तथा हमने यह उपलब्धि 2014 में हासिल कर ली थी। ई-विधान प्रणाली लागू होने से जहाँ विधायी कार्यों में दक्षता तथा पारदर्शिता आई वहीं पेपर के बोझ से भी काफी निजात मिल गई थी। हिमाचल प्रदेश ई-विधान ऐसी नवीनतम तकनीक है इसके जरिए मोबाईल ऐप सेवा, ई-निर्वाचन क्षेत्र प्रबंधन तथा ई-समिति के लागू होने से विधान सभा सदस्यों का सरकारी अधिकारियों तथा जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित हो गया था जिससे कार्य में दक्षता तथा पारदर्शिता दिखने लगी जिसका अनुसरण देश के लगभग 22 राज्य कर रहे थे। देश में डिजिटल इंडिया अभियान के तहत केन्द्र सरकार द्वारा (नेवा) राष्ट्रीय ई-विधान को पूरे भारत के राज्य विधान मण्डलों में लागू करने के लिए प्रेरित किया गया और अब हिमाचल प्रदेश ने भी राष्ट्रीय ई-विधान को अपना लिया है और अभी पूरी तरह अपनाने में थोड़ा सा समय और लग सकता है। विधान सभा अध्यक्ष यह बात सम्मेलन में आज के दिन चर्चा के लिए लाए गए विषय 'पारदर्शी, कुशल और नागरिक-केन्द्रित विधायी प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग भूमिका' पर अपना सम्बोधन दे रहे थे।

मुख्यमंत्री ने एनएसयूआई के 'चिट्टा मुक्त कैंपस' कार्यक्रम का किया शुभारम्भ

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज शिमला से एनएसयूआई जिला मंडी के 'चिट्टा मुक्त कैंपस' कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य स्कूल व कॉलेज परिसरों में युवाओं को नशे, विशेषकर चिट्टा के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें शिक्षा, खेल और सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एनएसयूआई मंडी का 'चिट्टा मुक्त कैंपस' अभियान प्रदेश सरकार के नशा मुक्त हिमाचल के विज़न को मजबूती प्रदान करता है तथा प्रदेश में चिट्टा सहित नशे के खिलाफ चलाए जा रहे राज्य सरकार के अभियान को और गति प्रदान करता है। उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए इस प्रकार के अभियान अत्यन्त आवश्यक होते हैं। एनएसयूआई जिला मण्डी के अध्यक्ष अनित जसवाल ने कहा कि यह अभियान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के 'एंटी-चिट्टा अभियान' से प्रेरित है और इसका उद्देश्य स्कूल व कॉलेज परिसरों को नशामुक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम, नशा विरोधी शपथ, एंटी-चिट्टा वॉकथॉन एवं स्पोर्ट्स टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे। अभियान 23 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा, जिसमें पहले स्कूल स्तर पर तथा बाद में कॉलेज स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे।

सोलन में आयुष मंत्री यादविंदर गोमा करेंगे ज़िला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता

सोलन। आयुष, युवा सेवाएं एवं खेल तथा विधि मंत्री यादविंदर गोमा सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में आयोजित होने वाले ज़िला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्यातिथि होंगे। यह जानकारी उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने दी।

मनमोहन शर्मा ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ज़िला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में आयोजित किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि मुख्यातिथि सर्वप्रथम प्रातः 10.40 बजे कारगिल शहीद स्मारक पर कृतज्ञ प्रदेश वासियों एवं ज़िला वासियों की ओर से शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उन्होंने कहा कि यादविंदर गोमा तदोपरांत प्रातः 11.00 बजे ठोडो मैदान में ध्वज फहराएंगे। मुख्यातिथि उसके उपरांत पुलिस तथा गृह रक्षा एवं अन्य टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत भव्य मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं अन्य को सम्मानित भी किया जाएगा। मनमोहन शर्मा ने सोलन निवासियों से आग्रह किया ज़िला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर बड़ी संख्या में ठोडो मैदान पहुंचे और कार्यक्रम का आनन्द उठाएं।

मुख्यमंत्री ने किए मनाली में 63.56 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज कुल्लू जिला के मनाली विधानसभा क्षेत्र के प्रवास के दौरान 63 करोड़ 55 लाख रुपये की 8 परियोजनाओं के उद्घाटन तथा शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ 69 लाख रुपये की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नथाण-जाणा सड़क के उन्नयन कार्य, 5 करोड़ 4 लाख रुपये की लागत से मनाली-कनयाल सड़क के स्तरोन्नत कार्य तथा नाबार्ड के तहत 13 करोड़ 19 लाख रुपये की लागत से निर्मित बबेली जिंदौड़ सड़क के मैटलिंग एवं टायरिंग कार्य का उद्घाटन किया। उन्होंने 13 करोड़ 52 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले 33/11 केवी जी.आई.एस. विद्युत सब-स्टेशन आईबैक्स चौक मनाली, 15 करोड़ रुपये की लागत से रांगडी में ब्यास नदी पर पुल के निर्माण, 2 करोड़ 90 लाख रुपये की लागत से रांगड़ी तथा बटाहर क्षेत्र के लिए ब्यास नदी के बाएं तट पर भूस्खलन नियंत्रण निवारण उपाय कार्य, एक करोड़ रुपये की लागत से कलाथ में हॉट वाटर स्नान सुविधा के कार्य तथा 2 करोड़ 22 लाख रुपये की लागत से जिला पंचायत संसाधन केंद्र, बाशिंग, कुल्लू का शिलान्यास भी किया।

मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए गए 1,116 निर्णय पूरी तरह कार्यान्वित: जगत सिंह नेगी

राजस्व एवं बागवानी मंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक

शिमला। राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक व औद्योगिक प्रशिक्षण एवं नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी, आयुष, युवा सेवाएं एवं खेल तथा विधि मंत्री यादविंद्र गोमा भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन को लेकर समीक्षा की गई। बैठक में अवगत करवाया गया कि 13 जनवरी, 2023 से 30 जून, 2025 तक मंत्रिमंडल की बैठकों में 1160 निर्णय लिए गए, जिनमें से 1,116 निर्णयों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा चुका है। शेष बचे 44 निर्णयों को लेकर चर्चा की गई, जिनमें वित्त, स्वास्थ्य, उद्योग, जलशक्ति, बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा, पर्यटन और परिवहन विभाग से जुड़े निर्णय शामिल हैं।जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को इन निर्णयों को समयबद्ध कार्यान्वित करने के निर्देश दिए ताकि आम जनता को लाभ मिल सके। नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि हमें प्रदेश की जनता को नहीं भूलना चाहिए। राज्य सरकार का हर अधिकारी और कर्मचारी लोगों के प्रति जवाबदेह है। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. नजीम, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्याम भगत नेगी, प्रधान सचिव देवेश कुमार, सदस्य सचिव हरबंस सिंह ब्रसकोन, सचिव डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस आशीष सिंहमार, निदेशक पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विवेक भाटिया और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

आवश्यक सूचना

पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया से पहले विज्ञापन में प्रकाशित किसी उत्पाद या सेवा के बारे में पूरी तरह जांच पड़ताल कर लें। यह समाचार पत्र उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता आदि के विवरण के बारे में विज्ञापनदाता द्वारा किये गये दावे उल्लेख की पुष्टि या समर्थन नहीं करता। समाचार पत्र उपरोक्त विज्ञापनों के बारे में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

RNI NO: HARHIN/2002/08034, Postal Regd No. HR/AB/54/23-25, स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक एकान्ति राय गर्ग द्वारा जनपथ पब्लिशर्स, बूथ नं.: 437-पी (बी.पी.पेट्रोल पंप के पीछे) सेक्टर-8, पंचकूला से प्रकाशित। **सम्पादक:- एकान्ति रॉय गर्ग,** मुख्य कार्यालय: बूथ नं: 437-पी (बी.पी.पेट्रोल पंप के पीछे) सेक्टर-8 पंचकूला-134109(हरियाणा)। मो.: 9915606900, email : hindjanpath@gmail.com, argarg1610@gmail.com ।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त राज्य बनाने के लिए 'गैंगस्टरां ते वार' की शुरुआत की

- गैंगस्टरों के खिलाफ निर्णायक जंग का उद्देश्य गैंगस्टरवाद को जड़ से खत्म करना: डीजीपी गौरव यादव
- 72 घंटे चलेगा ऑपरेशन प्रहार; 2000 से अधिक पुलिस टीमें 60 विदेशी गैंगस्टरों के साथियों से जुड़े ठिकानों पर कर रही हैं छापेमारी: डीजीपी गौरव यादव
- गैंगस्टरों की प्रत्यर्पण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ओवरसीज फ्यूजिटिव ट्रैकिंग एंड एक्स्ट्राडिशन सेल की स्थापना: डीजीपी गौरव यादव

हिन्द जनपथ
चंडीगढ़ (ब्यूरो)। राज्य से नशों के खात्मे के लिए चलाई गई मुहिम 'युद्ध नशेयां विरुद्ध' की जबरदस्त सफलता के बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने अब पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त राज्य बनाने के लिए 'गैंगस्टरां ते वार' अभियान के तहत गैंगस्टरों के खिलाफ एक निर्णायक जंग शुरू कर दी है।

इस जंग की घोषणा करते हुए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने कहा कि राज्य में गैंगस्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जिसमें 12,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती वाली 2000 पुलिस टीमें 60 विदेशी गैंगस्टरों के साथियों के चिन्हित और मैप किए गए ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। उन्होंने बताया कि यह छापेमारी 72 घंटे तक चलने वाले 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत की जा रही है।

आज यहां पंजाब पुलिस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट (पीपीओआई) में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डीजीपी गौरव यादव, जिनके साथ विशेष डीजीपी कानून एवं व्यवस्था अर्पित शुक्ला, एडीजीपी एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) प्रमोद बान और आईजीपी मुख्यालय डॉ. सुखचैन सिंह गिल भी मौजूद थे, ने गैंगस्टरवाद और इसका समर्थन करने वालों के खिलाफ पंजाब सरकार की जीरो-टॉलरेंस नीति को दोहराया।

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर एक सुव्यवस्थित और रणनीतिक जंग की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य गैंगस्टरवाद के पूरे इकोसिस्टम, जिसमें उनकी वित्त व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स, छिपने के ठिकाने, हथियारों की सप्लाई चेन और संचार नेटवर्क शामिल हैं, को पूरी तरह ध्वस्त करना है।

उन्होंने विदेशों में बैठे गैंगस्टरों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे खुद को विदेशों में सुरक्षित न समझें, क्योंकि जल्द ही उन्हें कानून का सामना करने के लिए पंजाब लाया जाएगा।

डीजीपी ने बताया कि पंजाब पुलिस ने ऐसे 60 गैंगस्टरों की पहचान की है, जो विदेशों में बैठकर अपने साथियों के माध्यम से पंजाब में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा, "इन विदेशी गैंगस्टरों की प्रत्यर्पण प्रक्रिया को तेज करने के लिए डीआईजी काउंटर इंटेलिजेंस आशीष चौधरी की अगुवाई में एक ओवरसीज फ्यूजिटिव ट्रैकिंग एंड एक्स्ट्राडिशन सेल (ओएफटीईसी) स्थापित किया गया है और जल्द ही ऐसे विदेशी गैंगस्टरों को कानून का सामना करने के लिए पंजाब लाया जाएगा।"

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि इन 60 विदेश आधारित पहचाने गये गैंगस्टरों में से 23 के खिलाफ पहले ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए जा चुके हैं या किए जा रहे हैं, जबकि शेष 37 गैंगस्टरों के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से 3 महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

डीजीपी ने भटके हुए युवाओं से अपील की कि वे अपराध का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में वापस लौटें। उन्होंने कहा, "मैं भटके हुए युवाओं से अपील करता हूं कि वे थोड़े से पैसों के लालच में विदेशी गैंगस्टरों के बहकावे में न आएं, क्योंकि जो खुद विदेशों में पनाह लेकर बैठे हैं, वे आपके हितैषी नहीं हो सकते।" उन्होंने चेतावनी दी कि जो युवा अपराध का यह रास्ता नहीं छोड़ेंगे, उन्हें सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा।

इस अवसर पर डीजीपी गौरव यादव ने एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 भी शुरू किया, जिसके जरिए लोग अपराधियों/गैंगस्टरों के बारे में गोपनीय रूप से जानकारी दे सकते हैं और अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं साझा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति द्वारा दी गई गैंगस्टरों से संबंधित सूचना के आधार पर यदि कोई गिरफ्तारी होती है, तो उसे 10 लाख रुपये तक की इनाम राशि देकर सम्मानित किया जाएगा।

न्यूज डायरी

'युद्ध नशेयां विरुद्ध' के 325वें दिन पंजाब पुलिस द्वारा 1.3 किलो हेरोइन सहित 76 नशा तस्कर गिरफ्तार

हिन्द जनपथ
चंडीगढ़ (ब्यूरो)। राज्य से नशों के पूर्ण उन्मूलन के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर शुरू की गई मुहिम "युद्ध नशेयां विरुद्ध" के 325वें दिन पंजाब पुलिस ने आज 369 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके बाद राज्य भर में 49 एफआईआर दर्ज करके 76 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इससे 325 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 45,403 हो गई है।

इन छापों के परिणामस्वरूप गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 1.3 किलो हेरोइन, 1 किलो अफीम, 18 किलो भुक्की, 130 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 2250 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के आदेश दिए हैं। पंजाब सरकार द्वारा नशों के खिलाफ जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति भी गठित की गई है।

इस ऑपरेशन के दौरान 70 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिस कर्मचारियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 369 स्थानों पर छापेमारी की है। उन्होंने आगे बताया कि दिन भर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 368 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की है।

बताने योग्य है कि पंजाब सरकार ने राज्य में नशों के उन्मूलन के लिए तीन-पक्षीय रणनीति - इन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (ईडीपी) - लागू की है और पंजाब पुलिस ने इस रणनीति के हिस्से के रूप में आज 37 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास का इलाज लेने के लिए राजी किया है।

विजिलेंस ब्यूरो ने 1.50 लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में सीवरमैन को किया गिरफ्तार

हिन्द जनपथ
चंडीगढ़ (ब्यूरो)। मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा अपनाई गई जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार विरोधी नीति के तहत पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने नगर निगम लुधियाना में तैनात सीवरमैन (नंबरदार) बहादर सिंह को 1 लाख 50 हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

आज यहां यह जानकारी देते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि यह गिरफ्तारी मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन पोर्टल पर फोकल प्वाइंट लुधियाना के गांव जमालपुर अवाणा के एक निवासी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की गई है।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आरोपी सीवरमैन ने उसे नगर निगम लुधियाना में सीवरमैन के रूप में भर्ती करवाने के बदले 1.50 लाख रुपये की रिश्वत तीन किस्तों में ली थी।

प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता ने आरोपी द्वारा रिश्वत की रकम लेते समय की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली थी। उल्लेखनीय है कि आरोपी बहादुर सिंह ने शिकायतकर्ता से लगभग ढाई साल तक सीवरेज की सफाई का काम भी करवाया, लेकिन इसके बदले उसे कोई वेतन नहीं दिया गया।

प्रवक्ता ने आगे कहा कि यदि जांच के दौरान इस मामले में नगर निगम लुधियाना के किसी अन्य अधिकारी की संलिप्तता सामने आती है तो उस अधिकारी के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जांच के दौरान उपरोक्त आरोप सही पाए गए हैं। इस संबंध में आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विजिलेंस ब्यूरो पुलिस थाना लुधियाना रेंज में मामला दर्ज कर लिया गया है तथा मामले की आगे की जांच जारी है।

"गैंगस्टरां ते वार": ऑपरेशन प्रहार के पहले दिन विदेश-आधारित गैंगस्टरों के 1300 से अधिक सहयोगी/साथी हिरासत में लिये

हिन्द जनपथ
चंडीगढ़ (ब्यूरो)। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार द्वारा पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए 'गैंगस्टरां ते वार' मुहिम शुरू करने के साथ पंजाब पुलिस की टीमों द्वारा आज ऑपरेशन प्रहार के पहले दिन विदेशी गैंगस्टरों के पहचाने गए और मैपड ठिकानों पर छापेमारी की गई।

गैंगस्टरों के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने कहा कि राज्य भर में 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत 72 घंटों की व्यापक कार्रवाई पहले से ही जारी है।

ऑपरेशन के पैमाने के बारे में बात करते हुए डीजीपी ने बताया कि 'ऑपरेशन प्रहार' के हिस्से के रूप में 12,000 पुलिस कर्मियों वाली 2000 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में विदेश-आधारित 60 गैंगस्टरों के सहयोगियों/साथियों से संबंधित पहचाने गए और मैपड ठिकानों पर छापेमारी की।

ऑपरेशन प्रहार के पहले दिन के नतीजे साझा करते हुए विशेष डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (विशेष डीजीपी) कानून एवं व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने कहा कि राज्य भर में विदेश-आधारित गैंगस्टरों के 1314 सहयोगियों/साथियों को हिरासत में लेकर पूरी बारीकी से जांच की जा रही है।

नागरिकों से संगठित अपराध के खिलाफ इस मुहिम में पंजाब पुलिस का साथ देने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी नागरिक गुप्त रूप से वांछित अपराधियों/गैंगस्टरों के बारे में एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर-93946-93946 के माध्यम से रिपोर्ट कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के अपराध तथा अपराधिक गतिविधियों के बारे में सूचना/जानकारी दे सकते हैं।

जेएसएस द्वारा आयोजित स्किल कन्वोकेशन में लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, सिलाई मशीनें तथा टूल किट्स वितरित किए गए

हिन्द जनपथ
चंडीगढ़ (ब्यूरो)। जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), चण्डीगढ़ द्वारा "स्किल कन्वोकेशन – 2026" का आयोजन जेएसएस परिसर, सेक्टर 38-ए, चंडीगढ़ में किया गया। इस कन्वोकेशन का उद्देश्य वर्ष 2024–25 के दौरान विभिन्न कौशल एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्णकरने वाले लाभार्थियों को सम्मानित करना था। संस्थान के निदेशक डॉ. अरविंद सिंघी ने जानकारी देते हुए बताया कि सफल प्रशिक्षुओं को उनके परिश्रम, कौशल अर्जन तथा आत्मनिर्भरता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम के अंतर्गत कटिंग एवं टेलरिंग पाठ्यक्रम के प्रशिक्षुओं को सिलाई मशीनें तथा ब्यूटी एंड वेलनेस पाठ्यक्रम एवं इलेक्ट्रिकल ट्रेड के छात्रों को टूल किट्स वितरित की गईं, ताकि वे स्वरोजगार प्रारंभ कर सकें और अपनी आजीविका के अवसरों को सुदृढ़ बना सकें। यह सभी उपकरण जन शिक्षण संस्थान की मातृ संस्था, एडल्ट एजुकेशन एसोसिएशन, यू.टी. चंडीगढ़ द्वारा प्रायोजित किए गए।\ इस अवसर पर प्रदीप कुमार, आईएएस, विशेष आयुक्त, नगर निगम, चंडीगढ़ ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। अपने संबोधन में उन्होंने युवाओं एवं महिलाओं को कौशल आधारित और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाने में जन शिक्षण संस्थान की भूमिका की सराहना की तथा आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में ऐसे प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान विकसित भारत 2047 के लिए पुनः समर्पण एवं शपथ ग्रहण समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से संस्थान ने कौशल विकास और समाज के वंचित वर्गों की क्षमता निर्माण के माध्यम से राष्ट्रीय विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया।

हरजोत बैंस द्वारा गैंगस्टरों के खिलाफ निर्णायक जंग के रूप में 'ऑपरेशन प्रहार' की सराहना

हिन्द जनपथ
चंडीगढ़ (ब्यूरो)। राज्य से गैंगस्टरवाद और आपराधिक ताकतों को जड़ से खत्म करने के लिए दृढ़ और स्पष्ट रुख अपनाते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री श्री हरजोत सिंह बैंस ने आज 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत गैंगस्टरों और समाज-विरोधी तत्वों के खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा की जा रही अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की सराहना की। यह ऑपरेशन पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की आतंकवाद, गैंगस्टरवाद और संगठित अपराध के प्रति जीरो-टॉलरेंस नीति को दर्शाता है।

श्री बैंस ने कहा, 'मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व में पंजाब की शान और सुरक्षा के लिए जंग की शुरुआत हो गई है।' उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस द्वारा गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 2,000 टीमें, जिनमें 12,000 से अधिक पुलिस कर्मचारी शामिल हैं, के साथ मिसाली कार्रवाई शुरू की गई है। पूरी फोर्स पंजाब से गैंगस्टरों को जड़ से खत्म करने में जुटी हुई है। पंजाब पुलिस के जज्बे और प्रतिबद्धता को सलाम करते हुए श्री बैंस ने कहा कि बीती देर रात शुरू हुए और 72 घंटे चलने वाले इस ऑपरेशन के दौरान पूरे तालमेल के साथ गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री मान व्यक्तिगत रूप से इस ऑपरेशन पर नजदीकी नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह शांति-कानून के दुश्मनों के खिलाफ जंग का ऐलान है। शिक्षा मंत्री ने अमृतसर और फतेहगढ़ साहिब में हुए पुलिस मुकाबलों की शुरुआती रिपोर्टों का हवाला देते हुए इस ऑपरेशन के दृढ़ इरादे और तुरंत कार्रवाई को सबूत के रूप में पेश किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इससे हमारे खूबसूरत राज्य और महान देश में अस्थिरता फैलाने की साजिशें नाकाम होंगी।

श्रम मंत्री सौंद द्वारा पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की योजनाओं और प्रक्रियाओं पर हैंडबुक जारी

- यह हैंडबुक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और निर्माण श्रमिकों को समय पर कल्याणकारी लाभ प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी – श्रम मंत्री

हिन्द जनपथ
चंडीगढ़ (ब्यूरो)। पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड द्वारा श्रम विभाग के साझेदारों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके दौरान श्रम मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने बोर्ड की योजनाओं और प्रक्रियाओं पर आधारित एक हैंडबुक जारी की।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की योजनाओं, प्रक्रियाओं और समय-सीमाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा निर्माण श्रमिकों को समय पर सहायता सुनिश्चित करने के लिए श्रमिक-हितैषी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना था। इस अवसर पर श्रम सुधारों पर एक पैनल चर्चा भी की गई, जिसमें क्रियान्वयन से जुड़ी चुनौतियों और क्षेत्रीय अनुभवों पर ध्यान केंद्रित किया गया। चर्चा के दौरान नए लेबर कोड्स के तहत बोर्ड की योजनाओं के प्रक्रियात्मक पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया और पारदर्शिता, अनुपालन में सहजता तथा साझेदारों के बीच समन्वय पर जोर दिया गया।

समारोह के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को सम्मानित किया गया और संबंधित उपायुक्तों को प्रशंसा पत्र भेंट किए गए। कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में बेहतर प्रदर्शन करने वाले सहायक श्रम आयुक्तों और श्रम निरीक्षकों को भी प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए।

अनुराग कुंडू, सदस्य पीडीसी तथा सचिव श्रम मनवेश सिंह सिद्धू ने बोर्ड द्वारा प्रक्रियाओं को सरल बनाने, अनावश्यक दस्तावेजों को कम करने और कल्याणकारी योजनाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए किए गए सुधारों पर प्रकाश डाला। इस दौरान निर्माण श्रमिकों तक पहुंच और सेवाएं प्रदान करने के संबंध में बोर्ड की उपलब्धियों को भी साझा किया गया।

राजीव गुप्ता, श्रम आयुक्त-सह-सचिव, पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, उप सचिव पदमजीत सिंह तथा पंजाब विकास आयोग के कर्मचारियों को हैंडबुक तैयार करने में उनके प्रयासों और अनावश्यक प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को कम करने हेतु की गई पहलों के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया।

इस कार्यक्रम में निदेशक ग्रामीण विकास अमित तलवार, डीसी संगरूर राहुल चब्बा, पटियाला और फाजिल्का के एडीसी, सहायक श्रम आयुक्त, उप निदेशक फैक्ट्रियां, श्रम निरीक्षक तथा पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड और श्रम कल्याण बोर्ड के कर्मचारी भी शामिल हुए।

विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने पेयजल की गुणवत्ता में गिरावट पर जताई गंभीर चिंता; बाकरपुर से लिए गए पानी के नमूने

हिन्द जनपथ
मोहाली (ब्यूरो)। पंजाब विधानसभा की बुड्ढा दरिया एवं घग्गर नदी से संबंधित मामलों की समिति की बैठक के दौरान डेराबस्सी के विधायक सरदार कुलजीत सिंह रंधावा ने अपने विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की गुणवत्ता में लगातार आ रही गिरावट को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। उक्त मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आज विधायक सरदार कुलजीत सिंह रंधावा की उपस्थिति में नोडल अधिकारी तहसीलदार, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड तथा थापर प्रयोगशाला के अधिकारियों द्वारा गांव बाकरपुर से पेयजल के नमूने एकत्र करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई।

इस अवसर पर विधायक रंधावा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पानी की गुणवत्ता की जांच पूर्ण पारदर्शिता के साथ की जाए और यदि किसी भी प्रकार की मिलावट अथवा प्रदूषण सामने आता है तो तत्काल सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि क्षेत्र के निवासियों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

जिला क्रिकेट संघ, मोहाली द्वारा अंडर-19 बालक क्रिकेट टीम के ट्रायल 27 जनवरी 2026 को आयोजित किए जाएंगे

हिन्द जनपथ
मोहाली (ब्यूरो)। जिला क्रिकेट संघ (डीसीए) मोहाली द्वारा अंडर-19 बालक क्रिकेट टीम के चयन हेतु ट्रायल 27 जनवरी 2026 को आयोजित किए जाएंगे। सभी पात्र एवं इच्छुक युवा क्रिकेट खिलाड़ियों को ट्रायल में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

स्थानः डीसीए मोहाली ग्राउंड, पीसीए स्टेडियम के पीछे, मोहाली

समयः प्रातः 10:00 बजे

सत्यापन एवं पात्रता सुनिश्चित करने हेतु खिलाड़ियों को निम्नलिखित दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य हैः

मूल जन्म प्रमाण पत्र (डिजिटल प्रारूप में)
आधार कार्ड
अन्य कोई प्रासंगिक सहायक दस्तावेज (यदि उपलब्ध हों)
उपरोक्त सभी दस्तावेजों की एक-एक फोटो प्रति

केवल वही खिलाड़ी ट्रायल में भाग लेने के पात्र होंगे जो पूर्ण, वैध एवं सत्यापन योग्य दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। संघ समय की पाबंदी एवं दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने पर विशेष जोर देता है।

प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि किसी भी अपडेट या अतिरिक्त जानकारी के लिए जिला क्रिकेट संघ, मोहाली के अधिकारियों के संपर्क में बने रहें।

मोहाली के MLA कुलवंत सिंह ने 11.38 km नई सड़कों के बनने का शुभारंभ किया

कहा, मोहाली विधानसभा क्षेत्र में 60 नई सड़कें और 32 खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं

- मोहाली में बिजली सुधार पर 750 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं
- भगवंत सिंह मान सरकार 22 जनवरी से 10 लाख की मुफ्त बीमा योजना शुरू करेगी

हिन्द जनपथ
मोहाली (ब्यूरो)। मोहाली विधानसभा क्षेत्र के MLA स. कुलवंत सिंह ने आज विधानसभा क्षेत्र के अलग-अलग गांवों की लिंक सड़कों और फुटपाथों के विकास के कामों का नींव पत्थर रखा। इन सड़कों की कुल लंबाई 11.38 km है, जिस पर लगभग 246.88 लाख रुपये खर्च होंगे। इन सभी सड़कों का काम 6 महीने में पूरा हो जाएगा।

इस मौके पर स. कुलवंत सिंह ने कहा कि इन सड़कों के बनने से गांवों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और लोगों को आने-जाने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि सभी काम तय स्टैंडर्ड के हिसाब से किए जाएंगे और सड़कों की लंबे समय तक मजबूती सुनिश्चित की जाएगी। इन सड़कों में 1.96 km लंबी नानूमाजरा-संभालकी-सुखगढ़-स्नेटा सड़क की मरम्मत 41.73 लाख रुपये की लागत से की जाएगी, जबकि 5 साल के मेंटेनेंस के लिए 3.33 लाख रुपये रखे गए हैं। सड़क का 420 मीटर हिस्सा पेवर ब्लॉक से और बाकी हिस्सा बजरी से पक्का किया जाएगा। गांव संभालकी की 0.75 km लंबी फिरनी की मरम्मत 11.58 लाख रुपये की लागत से की जाएगी और 5 साल के मेंटेनेंस के लिए 2.41 लाख रुपये रखे गए हैं। सड़क बजरी से बनेगी। खरड़-बनूर रोड से रायपुर कलां तक 1.10 km लंबी लिंक रोड की मरम्मत 16.20 लाख रुपये की लागत से की जाएगी। सड़क का 400 मीटर हिस्सा पेवर ब्लॉक से और बाकी हिस्सा बजरी से पक्का किया जाएगा। सैदपुर से चूहड़ माजरा तक 1 km लंबी सड़क की मरम्मत 19.52 लाख रुपये की लागत से की गई है और 5 साल के लिए रखरखाव के लिए 2.88 लाख रुपये रखे गए हैं। सड़क को एक लुक के साथ तैयार किया जाएगा।

गोबिंदगढ़ से ढेलपुर तक 2.17 km लंबी सड़क की मरम्मत 41.16 लाख रुपये की लागत से की जाएगी और 5.64 लाख रुपये 5 साल के लिए रखरखाव के लिए रखे गए हैं। सड़क को एक लुक के साथ तैयार किया जाएगा।

ढेलपुर से गदाना तक 1.19 km लंबी लिंक रोड की मरम्मत 19.67 लाख रुपये की लागत से की जाएगी, जबकि 5 साल के लिए रखरखाव के लिए 2.40 लाख रुपये रखे गए हैं।

गीगा माजरा की 0.88 km लंबी सड़क को 24.86 लाख रुपये की लागत से 60 mm पेवर ब्लॉक लगाकर तैयार किया जाएगा। मनौली-स्याऊ लिंक रोड और प्रेमगढ़ अप्रोच रोड (2.33 km लंबी) की मरम्मत 48.47 लाख रुपये और 5 साल के मेंटेनेंस के लिए 7.04 लाख रुपये की लागत से की गई है। सड़क को आकर्षक लुक दिया जाएगा।

MLA कुलवंत सिंह ने कहा कि मोहाली विधानसभा क्षेत्र में 60 नई सड़कें और 32 नए स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को बेहतर ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिल सके और युवा खेलों से जुड़ सकें।

उन्होंने कहा कि मोहाली में बिजली सुधार का काम भी चल रहा है और पूरे पंजाब के लिए 5000 करोड़ रुपये के बिजली अपग्रेड बजट में से 750 करोड़ रुपये मोहाली में खर्च किए जा रहे हैं। MLA कुलवंत सिंह ने कहा कि लोगों को बिजली बिल में 300 यूनिट फ्री देने, आम आदमी क्लीनिक के ज़रिए फ्री दवाइयां और ज़रूरी टेस्ट देने और अच्छी शिक्षा के लिए पूरे पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाने के अलावा, पंजाब के लोगों के लिए हेल्थ केयर गारंटी के तौर पर 22 जनवरी को मुख्यमंत्री हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम शुरू की जा रही है, जिसके तहत पंजाब के करीब 65 लाख परिवारों को 10 लाख रुपये तक का फ्री इलाज मिलेगा।

संपादकीय

क्या शिंदे की शिवसेना पर भारी पड़ेगी 'बड़े भाई' की दावेदारी?

बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) चुनाव में भाजपा नीत गठबंधन 'महायुति' ने जीत का परचम लहरा दिया है। साथ ही अविभाजित शिवसेना की लगातार ढाई दशक से चली आ रही सत्ता की विरासत को भी छीन लिया है। भाजपा इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जो उसके बढ़ते जनाधार का संकेत है।वहीं, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना भले हार गई, मगर वह अपनी कुछ साख बचाने में कामयाब रही है। अब सवाल यह है कि बीएमसी का नया महापौर कौन होगा और महायुति में शामिल किस दल का होगा? इसको लेकर जीत हासिल करने वाले गठबंधन के बीच जोर-आजमाइश भी शुरू हो गई है।हालांकि, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को भाजपा से काफी कम सीटों पर जीत हासिल हुई है, मगर वह महापौर की दावेदारी में बनी हुई है। सवालों और सियासत के इस क्रम में यह उम्मीद ज्यादा महत्त्वपूर्ण है कि बीएमसी की नई सत्ता मुंबई के संपूर्ण विकास के नए द्वार खोलेगी। बीएमसी को देश का सबसे अमीर निगम माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका बजट, जो देश के कई छोटे राज्यों के बजट से कहीं ज्यादा होता है। यही कारण है कि बीएमसी चुनाव की सिर्फ मुंबई में ही नहीं, बल्कि देश भर में चर्चा होती है। पिछले 25 वर्षों से बीएमसी में अविभाजित शिवसेना की सत्ता रही है। मगर, इस बार के चुनाव में भाजपा नीत महायुति ने शिवसेना के इस किले में ऐसी सेंध लगाई कि उसे सत्ता से बेदखल कर दिया। अब सवाल यह है कि बीएमसी का महापौर भाजपा का होगा या फिर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का। देखा जाए तो बीएमसी चुनाव में भाजपा ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं और इस लिहाज से महापौर के लिए उसकी दावेदारी सबसे ऊपर है। मगर शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने इस पर अभी तक अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट नहीं किया है। अब ऐसी भी खबरें आई हैं कि शिवसेना महापौर का पद पाने के लिए भाजपा पर दबाव बना सकती है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उनका तर्क है कि आर्कटिक क्षेत्र भविष्य की सामरिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बनने जा रहा है और ग्रीनलैंड इस पूरे क्षेत्र की चाबी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वैश्विक राजनीति में उथल पुथल मचा दी है। इस बार विवाद का केंद्र बना है ग्रीनलैंड। ट्रंप ने संकेत दिया है कि दुनिया के जो देश ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की रणनीति का समर्थन नहीं करेंगे, उन पर अमेरिका भारी टैरिफ लगा सकता है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की सक्रियता तेजी से बढ़ रही है और अमेरिका वहां अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है।

ग्रीनलैंड पर दुनिया को ट्रंप की टैरिफ धमकी, जो विरोध करेगा उस पर लगाएंगे टैरिफ

(नीरज कुमार दुबे)

डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उनका तर्क है कि आर्कटिक क्षेत्र भविष्य की सामरिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बनने जा रहा है और ग्रीनलैंड इस पूरे क्षेत्र की चाबी है। उन्होंने साफ संकेत दिया कि जो देश इस अमेरिकी सोच के साथ नहीं आएंगे, उन्हें आर्थिक कीमत चुकानी पड़ सकती है।

हम आपको बता दें कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है और डेनमार्क सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ग्रीनलैंड न तो बिकाऊ है और न ही किसी दबाव में सौंपा जा सकता है। ग्रीनलैंड के स्थानीय प्रशासन ने भी अमेरिका की इस सोच को खारिज करते हुए कहा है कि वहां के लोग अपने भविष्य का फैसला खुद करेंगे। वहीं यूरोप के कई देशों ने डेनमार्क के समर्थन में बयान दिए हैं और इसे अंतरराष्ट्रीय नियमों और संप्रभुता के खिलाफ बताया है। साथ ही ट्रंप की टैरिफ धमकी को कई देशों ने आर्थिक जबरदस्ती करार दिया है। ट्रंप के ताजा बयान के बाद ट्रांस अटलांटिक रिश्तों में तनाव साफ दिखाई देने लगा है और नाटो के भीतर भी असहजता बढ़ती नजर आ रही है। देखा जाये तो डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड को लेकर दिया गया बयान एक ऐसी राजनीति को उजागर करता है जिसमें कूटनीति नहीं बल्कि धमकी हथियार बन चुकी है।

ग्रीनलैंड क्यों अहम है यदि इसकी बात करें तो आपको बता दें कि यह कोई साधारण बर्फीला द्वीप नहीं है। यह आर्कटिक क्षेत्र में स्थित एक ऐसा भूभाग है जहां से उत्तरी अटलांटिक पर नजर रखी जा सकती है। यहां दुर्लभ खनिज संसाधन हैं। यहां से मिसाइल

चेतावनी प्रणाली, नौसैनिक गतिविधियां और वायु मार्ग नियंत्रित किए जा सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका इसे केवल आर्थिक नहीं बल्कि सैन्य नजरिये से भी देखता है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि ग्रीनलैंड कितना महत्वपूर्ण है। असली सवाल यह है कि क्या किसी देश को यह अधिकार है कि वह अपनी सामरिक जरूरतों के नाम पर दूसरे देशों पर आर्थिक दबाव बनाए। ट्रंप का बयान इसी सोच की खतरनाक मिसाल है। देखा जाये तो टैरिफ अब अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। टैरिफ का इस्तेमाल कभी व्यापार संतुलन के लिए होता था। आज यह राजनीतिक और सामरिक दबाव का औजार बन गया है। ट्रंप की धमकी बताती है कि अमेरिका अब खुले तौर पर कह रहा है या तो हमारे साथ खड़े हो जाओ या आर्थिक सजा भुगतो। यह नीति न केवल वैश्विक व्यापार को नुकसान पहुंचाती है बल्कि छोटे और मध्यम देशों को डर के साए में जीने पर मजबूर करती है। आज ग्रीनलैंड है। कल कोई और मुद्दा होगा। यह रवैया पूरी दुनिया को अस्थिरता की ओर धकेल सकता है।

दूसरी ओर, नाटो की नींव सामूहिक सुरक्षा और आपसी भरोसे पर टिकी है। लेकिन जब नाटो का सबसे शक्तिशाली सदस्य ही दूसरे सदस्य देश पर दबाव डालने लगे, तो यह गठबंधन कैसे टिकेगा। डेनमार्क नाटो का सदस्य है। ग्रीनलैंड उसका हिस्सा है। अगर अमेरिका उसी देश को धमकी दे रहा है, तो यह नाटो पर सीधा हमला है। यह संदेश जा रहा है कि गठबंधन तभी तक मान्य है जब तक वह अमेरिकी हितों के अनुकूल है। इस बीच, यूरोप के कई देशों के भीतर अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या अमेरिका सच में भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार है या नहीं। यह वही दरार है जो नाटो को अंदर से खोखला कर सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर आक्रामक रुख अपनाता है, तो इसके दूरगामी सामरिक परिणाम होंगे। रूस और चीन को यह कहने का मौका मिलेगा कि पश्चिमी देश दोहरे मानदंड अपनाते हैं। ऐसे में यूरोप अपने स्वतंत्र रक्षा ढांचे की ओर और तेजी से बढ़ सकता है। इससे नए सैन्य और आर्थिक गुट बन सकते हैं। इसका मतलब यह भी है कि दुनिया एक बार फिर गुटों में बंटने की ओर बढ़ेगी। शीत युद्ध जैसी स्थिति लौट सकती है लेकिन इस बार आर्थिक हथियार ज्यादा खतरनाक होंगे। अब सवाल उठता है कि क्या नाटो खत्म होने की कगार पर है? जवाब यह है कि नाटो तुरंत खत्म नहीं होगा। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि वह अपने सबसे नाजुक दौर में है। अगर अमेरिका इसी तरह सहयोगियों पर दबाव डालता रहा, तो नाटो का अस्तित्व केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा। देखा जाये तो किसी भी गठबंधन की ताकत हथियारों से नहीं, भरोसे से आती है। और भरोसा तब टूटता है जब धमकी संवाद की जगह ले ले। बहरहाल, डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड को लेकर दिया गया बयान एक चेतावनी है। यह चेतावनी है उस दुनिया के लिए जो नियम आधारित व्यवस्था पर भरोसा करती रही है। यह संकेत है कि आने वाले समय में ताकतवर देश ज्यादा आक्रामक और ज्यादा बेपरवाह हो सकते हैं। अगर इस सोच को समय रहते रोका नहीं गया, तो न केवल नाटो बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था गहरे संकट में फंस सकती है। ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे केवल खनिज नहीं हैं, वहां भविष्य के टकराव की चिंगारी भी छुपी हुई है।

रूस-चीन की दिलचस्पी सैनिक कार्रवाई रही नहीं

(उमेश चतुर्वेदी)

पिछली सदी के आखिरी दशक तक, जब तक सोवियत संघ अस्तित्व में रहा, कम से कम दुनिया के कमजोर और साधनहीन देशों को उम्मीद रहती थी कि अगर अमेरिका ने उनकी ओर आंख तरेरी तो सोवियत संघ का साथ मिलेगा और अगर सोवियत संघ ने निगाहें तीखी कीं तो अमेरिका उसकी मदद करने पहुंचेगा। साल 2026 के तीसरे ही दिन अमेरिका ने जिस तरह वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की, उसके बाद से विशेषकर सैनिक रूप से कमजोर देशों में चिंता की लहर है। चाहे अमेरिकी खेमे में हो या फिर अमेरिका विरोधी खेमे में, हर देश आशंकित हो उठा है। अमेरिका के सर्वोच्च पद पर डोनॉल्ड ट्रंप के रहते ऐसी चिंताएं स्वाभाविक भी हैं। जिस तरह अपने ही खेमे के देश डेनमार्क के ग्रीनलैंड द्वीप पर ट्रंप ने अपनी नजर टिका रखी है, उससे दुनिया को चिंतित होना ही चाहिए। ऐसे में विश्व की निगाह दुनिया के सैनिक रूप से दूसरे शक्तिशाली देश रूस और आर्थिक रूप से दूसरे और सैनिक रूप से तीसरे ताकतवर देश चीन पर लगना स्वाभाविक है। लेकिन दोनों ही देशों ने वेनेजुएला पर जिस तरह रस्मी प्रतिक्रिया जताई है, उससे लगता नहीं कि वे भविष्य में ऐसी अमेरिकी कार्रवाइयों के खिलाफ अपने मित्र देशों के पक्ष में खड़े होने आएंगे। पिछली सदी के आखिरी दशक तक, जब तक सोवियत संघ अस्तित्व में रहा, कम से कम दुनिया

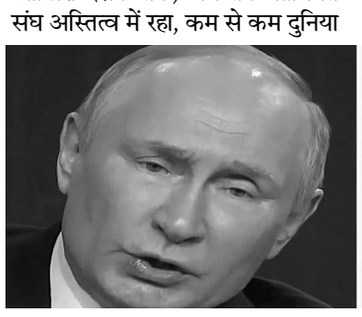

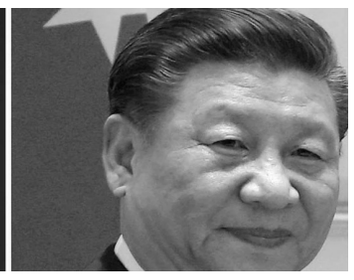

के कमजोर और साधनहीन देशों को उम्मीद रहती थी कि अगर अमेरिका ने उनकी ओर आंख तरेरी तो सोवियत संघ का साथ मिलेगा और अगर सोवियत संघ ने निगाहें तीखी कीं तो अमेरिका उसकी मदद करने पहुंचेगा। सोवियत संघ के विघटन के बाद उसका सबसे बड़ा हिस्सा रूस शक्तिशाली तो बना रहा है, लेकिन मौजूदा अमेरिका-ब्रिटेन प्रेरित-पोषित आर्थिक दुनिया में सोवियत संघ जैसी ताकत बना नहीं रह सका। सोवियत संघ के वजूद में रहते तक विश्व में खुलेतौर पर दो दुनिया थी और दो मुद्राओं का जोर भी था। बेशक डॉलर, सोवियत और आज के रूस की मुद्रा रूबल की तुलना में ताकतवर था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि आर्थिक रूप से पूरी दुनिया को नियंत्रित कर सके। लेकिन आज आर्थिक क्षेत्र में डॉलर को कोई चुनौती नहीं है। ब्रिक्स देशों ने अपनी-अपनी मुद्राओं को आपसी आर्थिक व्यवहार में आगे बढ़ाने की कोशिश तो की है, हालांकि वह डॉलर को चुनौती देने की स्थिति में नहीं आ पाई हैं। अमेरिका जानता है कि उसकी आर्थिक ताकत को बड़े स्तर पर चुनौती देने की हालत में दुनिया की दूसरी यानी चीन की अर्थव्यवस्था नहीं है, इसलिए ट्रंप बेफिक्र होकर कभी मैक्सिको को अपना उपनिवेश बनाने की वकालत करते हैं तो कभी कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का ऐलान करते हैं। ग्रीनलैंड पर निगाह और वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई उनकी इसी सोच का विस्तार है। वेनेजुएला पर कार्रवाई को लेकर रूस और चीन ने चिंताएं तो जाहिर कीं, लेकिन वे वेनेजुएला को सैनिक सहयोग करने के लिए इच्छुक नहीं दिखे। इसकी मोटे तौर पर दो वजहें सामने आती हैं। वेनेजुएला से रूस ने 2010 में समझौता तो किया, लेकिन वह रणनीतिक, तकनीकी और आर्थिक मामलों पर केंद्रित है। सैनिक सहयोग की बात उसमें नहीं है। दिलचस्प यह है कि वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार का सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला चीन भी इस मामले में उसको सैनिक सहयोग करने से दूर है। वेनेजुएला के तेल निर्यात का 50 से 89 प्रतिशत तक हिस्सा सिर्फ चीन जाता था। मोटे तौर पर चीन रोजाना वेनेजुएला से चार लाख बैरल से लेकर छह लाख साठ हजार बैरल तेल आयात कर रहा था। इसके बावजूद वह वेनेजुएला को सैनिक सहायता देने से हिचक रहा है। चीन की स्थिति यह है कि वह एशिया में अपनी सैन्य ताकत का गाहे-बगाहे मुजाहिरा तो करता है, लेकिन वह सुदूर दक्षिणी अमेरिकी या अफ्रीकी महाद्वीप के देशों में ऐसा करने से हिचक रहा है। इसकी वजह यह है कि चीन की नीतियां कम से कम एशिया से बाहर सिर्फ और सिर्फ आर्थिक मुद्दों पर ही टिकी हैं। पारंपरिक भारतीय शब्दावली में कह सकते हैं कि चीन बनिया बन चुका है। यानी उसका पूरा ध्यान आर्थिक लाभ और हानि पर है। फिर ट्रंप काल में अमेरिका से कारोबारी मुद्दे पर उसकी ठनी हुई है। जिसे वह सहज करने की कोशिश में है। इसलिए वह कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता, जिससे ट्रंप नाराज हों और अमेरिका से उसके कारोबारी रिश्तों पर असर पड़े। चीन की पूरी कोशिश अमेरिका से जारी व्यापार युद्ध को खत्म करे और आर्थिक मोर्चे पर अपनी ताकत बढ़ाए। उसकी कोशिश किसी तरह अमेरिका को खुश करने की भी होगी, ताकि वेनेजुएला से वह पहले की तरह तेल का भारी आयात कर सके। वेनेजुएला के मसले पर रूस की भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। रूस यूक्रेन में फंसा हुआ है। वेनेजुएला से रूस की रणनीतिक संधि तो है, लेकिन उसमें साझा रक्षा का जिक्र नहीं है। फिर रूस के संसाधन, सेना, सैन्य उपकरण आदि यूक्रेन युद्ध में लगे हुए हैं। ऐसे में अगर वह वेनेजुएला का सैन्य सहयोग करता है तो एक तरह से वह अमेरिका के खिलाफ नया मोर्चा खोलना होगा। रूस इस वजह से बचना चाहता है। इसीलिए जब रूसी झंडा लगे पोत को अमेरिकी सेना ने रोका तो रूस ने सिर्फ अमेरिका से रूसी नागरिकों की हिफाजत और उन्हें छोड़ने की अपील ही की। अतीत में जब सोवियत संघ था, तब अमेरिका ऐसी हिम्मत ही नहीं करता था और अगर करता भी तो सोवियत सेनाएं उस ओर कूच कर सकती थीं। जाहिर है कि लगातार अर्थकेंद्रित होती दुनिया में देशों की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। किसी मसले को सुलझाने के लिए सैन्य कार्रवाई अब आखिरी विकल्प के तौर पर उभरी है। रूस और चीन इसी मानस से ग्रस्त हैं। इसीलिए वेनेजुएला ही नहीं, ऐसे अपने किसी और साथी के सहयोग के लिए सक्रिय रूप से सामने आने में अब उनकी दिलचस्पी नहीं है। ऐसे में दुनिया, विशेषकर अमेरिकी कोप से आशंकित देशों को चिंतित होने की जरूरत है। उन्हें वैकल्पिक राह भी तलाशनी होगी। लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तम्भकार हैं

वर्ग पहेली 5980

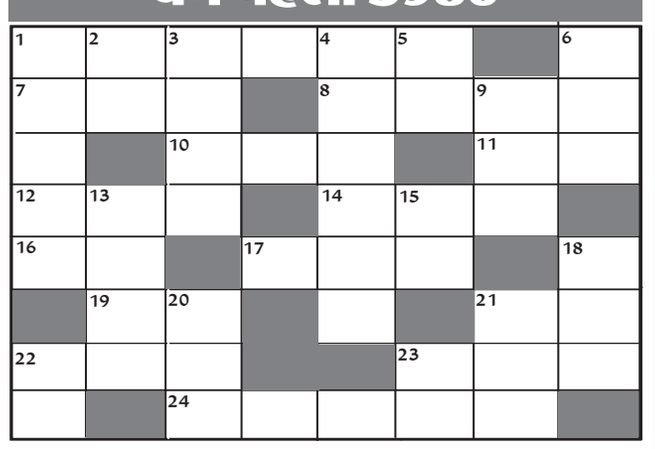

संकेतः बाएं से दाएं

1. डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक और प्रमुख राजनीतिज्ञ की आज पुण्य तिथि है (6)
7. सिंचाई आदि के लिए बनाया गया कृत्रिम जलमार्ग (3)
8. मुंह या किनारे तक, लबालब (4)
10. येन मुद्रा का प्रचलन इस देश में है (3)
11. जंगल, अरण्य, कानन (2)
12. खरी-खोटी कहना, श्रवण कराना (3)
14. रसीद, पहुंच पत्र, प्राप्ति की स्वीकृति (3)
16. शास्त्रीय संगीत में स्वर का विस्तार, तानने की क्रिया (2)
17. समा जाना (3)
19. चौकोर चीज, पांसा (2)
21. दीर्घ मात्रा (2)
22. सौ करोड़ की संख्या (3)
23. कक्षा, समुदाय, संघ (3)
24. भगवान श्रीरामचंद्र के नामों में से एक (5)

ऊपर से नीचे

1. जनक की पुत्री होने के कारण सीता का एक नाम (5)
2. एक प्रशंसा सूचक शब्द, धन्व (2)
3. हानि का बदला, क्षतिपूर्ति (4)
4. प्रेम करना और पालना (6)
5. अधर, रदपट, ओंठ, ओष्ठ (2)
6. स्वकुल, आत्मीयजन, अपने लोग (3)
9. सत्ताईस नक्षत्रों में से अंतिम नक्षत्र, पुराणानुसार राजा रेवत की पुत्री बलराम की पत्नी थी (3)
13. सेवक को जीविका हेतु पुरस्कार में दी जाने वाली जमीन यह कहलाती थी (4)
15. अवस्था, उम्र (2)
18. यह लेबनान की राजधानी है (3)
20. इस मुगल शासक का मूल नाम जहीरूद्दीन मुहम्मद बादशाह था, इसका अरबी शब्द का अर्थ बाघ होती है (3)
21. बदगुमानी, कुधारणा (3)
22. यह एक राजनीतिक पार्टी का संक्षिप्त नाम है(2)

वर्ग पहेली 5979 का हल

अ	मी	र	खु	स	रो	■	■
दा	ना	■	द	हे	ज	■	ज
■	र	जा	■	ली	ना	■	न
भू	■	म	म	■	म	म	ता
■	सा	वं	त	■	चा	ल	■
कु	■	त	ल	ब	■	य	क्ष
वै	ट	■	बी	ना	■	गि	■
त	ब	का	■	ना	ग	रि	क

हिन्दी सिनेमा और गीत साहित्य

(डॉ. सुधा कुमारी)

हिन्दी सिनेमा में कई गीतकारों ने सुन्दर सार्थक गीत लिखे हैं जिनमें दार्शनिकता, भक्ति, प्रेम, देशभक्ति, शिशु गीत हैं। कुछ फिल्मी गीतों को सामाजिक उत्सवों में स्थान दिया जाने लगा है। फिर भी फिल्मी होने के कारण उन्हें पुस्तकों से दूर रखा जाता है, हिंदी साहित्य में स्थान नहीं मिलता। कई बार तो साहित्यिक सुन्दर गीत भी ग्लैमर के दृश्य में दिखाकर उनकी गुणवत्ता कम की जाती है और दर्शक साहित्य को भूलकर स्वप्न-लोक जैसे परिदृश्य देखने में ही लीन रहता है। जहां उत्तम साहित्य का उद्देश्य मनुष्य को अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाना है, पशु-प्रवृत्ति से मनुष्यत्व की ओर ले जाना है, कालजयी साहित्य बनाना है, वहां फिल्म का उद्देश्य मात्र मनोरंजन है। दोनों अपने-अपने उद्देश्य के लिए उसी प्रकार से कार्य करते हैं।

सिनेमा ऑडियो विजुअल माध्यम है और फिल्म निर्माण और विज्ञापन के लिए बहुत धन की आवश्यकता होती है। सिनेमा व्यवसायिक सफलता के चक्रव्यूह में फंसा है और प्रसिद्धि पाने के उसके प्रयास व्यवसायिक लाभ के अनुसार किये जाते हैं, कालजयी साहित्य बनाने के अनुसार नहीं। व्यवसायिक लाभ के लिए इस में मारपीट, शराब-जुआखाना, ग्लैमर, जोर-शोर वाले नृत्य-गीत दिखाए जाते हैं ताकि उनके आकर्षण में आम जनता फ़िल्म देखने जाये, भले ही उसके गीत निरर्थक शब्दों वाले ही क्यों न हों। तेज गति के संगीत (जिसे संगीत कहना भी संगीत के साथ अन्याय ही होगा) और ग्लैमर के मचान के सहारे कई बार तो निरर्थक गीत भी अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि का शिखर पा लेते हैं। ऐसे में सफल लोगों की संगति पाने के लिए अच्छे-अच्छे गीतकार को भी साहित्यिक और सार्थक गीतों से समझौता करना पड़ सकता है।

किसी भी कविता या गीत को साहित्य में सम्मिलित करने के लिए पर्याप्त प्रयास करना होता है। जिन साहित्यकारों को यह सौभाग्य मिला है, वे इस विषय पर मार्गदर्शन कर सकते हैं। यदि फिल्म गीतकार गीतों को लिखकर उन्हें प्रकाशित करवाएं या शिक्षा विभाग को भिजवाए तो शायद सफलता मिल सकती है पर गीतकार इतना प्रयास नहीं कर पाते। फिल्म की सफलता और धन उनकी गृहस्थी की गाड़ी चलायमान रखते हैं। और फिल्म निर्माता अपने लिए अपार धन को चुनता है, गीतकारों की अनंत कीर्ति को नहीं।

एक उदाहरण है- भोजपुरी और मैथिली का जो क्षेत्रीय बोलियां हुआ करती थीं। जहां भोजपुरी ने ऑडियो विजुअल माध्यम सिनेमा को अपना लक्ष्य बनाया और घुँघरू की छमछम, ढोल की थाप, द्विअर्थी शब्दों के जाल में में खो गया, वहीं मैथिली ने गीत, उपन्यास, कथा, डाक्यूमेंट्री आदि पर ध्यान केंद्रित कर साहित्य का पर्याप्त भण्डार सृजन किया और एक दिन संविधान की 8वीं अनुसूची में एक साहित्यिक भाषा के रूप में स्थान पा लिया। भोजपुरी आज भी बोली है, भाषा नहीं। इसके गीत आज भी आम जनता में लोकप्रिय हैं पर साहित्य की श्रेणी में नहीं आते।

हिंदी साहित्य ऐसे सार्थक गीतों को अपने हृदय में जगह देता है या नहीं, यह लोगों के प्रयास और प्रभाव पर निर्भर करेगा। पर यदि आम जनता शीला और मुन्नी की चुन्नी में ही उलझी रहेगी तो साहित्य क्या करे? ऊपर व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं।

आज का राशिफल

मेष

आज आपकी रुचि जप-तप, यज्ञ और भगवान की भक्ति में अधिक रहेगी। आज सामाजिक व धार्मिक कार्यों में सहयोग करेंगे। आज आपके अच्छे कार्यों से आपका व आपके परिवार का गौरव बढ़ेगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता का लाभ भी आपको मिलेगा।

वृष

वृष राशि के जातकों को संतान पक्ष के श्रेष्ठ आचरण और उनकी सफलता से हर्ष होगा। माता-पिता से आशीर्वाद लेकर घर से निकलें कोई विशेष सफलता मिलेगी। नौकर-चाकर व सांसारिक सुख भोगों का विस्तार होगा।

मिथुन

अगर कोई मुकदमा या कोई अन्य पूछताछ चल रही है तो आज समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। त्वरित निर्णय न ले पाने के कारण कार्यों में बाधा व हानि होगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो अधिकारियों की कृपा से अधिकारों में वृद्धि हो सकती है।

कर्क

आज करियर में प्रमोशन का दिन है। इसके अतिरिक्त आज आप अपनी वाक्पटुता से किसी बहुत बड़े अफसर को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे। नेत्र विकारों से परेशानी में कमी आएगी। निर्णय लेने की क्षमता का लाभ होगा।

सिंह

आज व्यापारी लोगों को व्यापार में कुछ नए परिवर्तन होंगे। नौकरी पेशा लोगों के अधिकार बढ़ेंगे, जिससे आपको आर्थिक लाभ व सम्मान मिलेगा। परिवार की तरफ से भी शुभ समाचार मिलेगा।

कन्या

आज अधिकारों में वृद्धि के साथ-साथ उत्तरदायित्व भी बढ़ेंगे। अपनी शान शौकत के लिए आप धन खर्च कर सकते हैं। आप दूसरों की भलाई व सेवा मन लगाकर दिल से करते रहे हैं। इसका लाभ आज आपकी संतान को मिलेगा।

र

तुला

आज काफी सोच विचार कर काम करने के उपरान्त भी नुकसान होने की संभावना रहेगी। अकस्मात् कोई राजकीय दण्ड भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए जोखिम के कामों से दूर रहें। सायंकाल से लेकर रात्रि तक भी छोटे-मोटे कष्ट व मान हानि की संभावना बनी रहेगी।

वृश्चिक

आज किसी बहुमूल्य वस्तु से लाभ होने की संभावना रहेगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो पद एवं अधिकारों में वृद्धि होगी। आप के साहस एवं पराक्रम के सामने शत्रु नतमस्तक होंगे। संतान के प्रति आपकी प्रेम भावना बढ़ेगी।

धनु

आज गुरु के प्रति निष्ठा एवं भक्ति भाव पूर्ण रहेगा। इस समय में अध्यात्म से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। आपकी बुद्धि विवेक नए-नए खोज करने में लगेगी। ऐसे में रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। सायंकाल में अकस्मात् संतान कष्ट होने का योग है। विश्वास प्राप्त व्यक्ति एवं नौकर चाकर विश्वासघात करने का प्रयास करेंगे सावधान रहें।

मकर

आज शारीरिक शक्ति एवं उत्साह अधिक रहेगा। हालांकि, ऐसे अनावश्यक खर्चे सामने आयेंगे, जो कि न चाहते हुए भी मजबूरी में करने पड़ेंगे। यदि आपका प्रमोशन रुका हुई है तो अवश्य प्राप्त हो जाएगा। आपके हाथ में बड़ी मात्रा में पैसा आने से हर्ष होगा।

कुंभ

आज धैर्य से काम लेना होगा। जल्दबाजी में किए गए कार्य से हानि होने की संभावना रहेगी। आपकी भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। नए-नए कार्यों में विनिमय करना पड़े तो अवश्य करें। आगे चलकर लाभ होगा।

मीन

आज आप स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहेंगे। पाचन क्रिया मंद एवं पेट में वायु विकार संबंधित कष्ट हो सकता है। यदि आप किसी वित्तीय संस्था या व्यक्ति से ऋण लेना चाहते हैं तो आसानी से मिल जाएगा। नई-नई योजनाएं बनाकर उन्हें सफल बनाने का पूर्ण प्रयास करें।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील 3 महीने में हो जाएगी ?

सीईओ ने प्लान बताकर ये दी नसीहत

नई दिल्ली, एजेंसी। दुनियाभर में अनिश्चितता का माहौल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियां इसकी एक बड़ी वजह है। इस बीच अमेरिका-भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम (यूएसआईएसपीएफ) के प्रेसीडेंट और सीईओ मुकेश अघी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ), दावोस में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते और दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि अगले तीन महीनों में एक व्यापारिक समझौता होने की संभावना है। अघी ने यह भी बताया कि अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश कम करने या अपनी सप्लाई चेन को कहीं और ले जाने की योजना नहीं बना रही हैं। सप्लाई चेन का मतलब सामान बनाने और पहुंचाने की व्यवस्था से है। मुकेश अघी ने

बिजनेस टुडे टीवी को दिए एक खास इंटरव्यू में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक व्यापार समझौते की राह आसान हो रही है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच बातचीत कई दौर से गुजर चुकी है और अब अंतिम चरण में है। अघी ने उम्मीद जताई कि अगले 3 महीनों में किसी तरह का व्यापार समझौता हो जाएगा। दोनों देश कृषि जैसे जटिल मुद्दों पर भी मिलकर काम कर रहे हैं, जो पिछले समझौतों की तुलना में तकनीकी रूप से ज्यादा पेचीदा रहा है। जब उनसे विश्वास के मुद्दे पर सवाल किया गया, खासकर हाल के टैरिफ और अप्रत्याशितता की चिंताओं को लेकर तो अघी ने माना कि कई देशों को ऐसी सरकार के साथ बातचीत करने में दुविधा होती है जो व्यापार नीति पर अस्थिर मानी जाती है। फिर भी, उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते की मजबूती को राजनीतिक बयानों के बजाय उसके पदार्थ और आपसी प्रतिबद्धताओं के आधार पर आंकना चाहिए।

अदाणी समूह लगाएगा 1600 मेगावाट का पावर प्लांट

सस्ती बिजली के साथ पैदा होंगे रोजगार के अवसर

नई दिल्ली, एजेंसी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की सदर तहसील के ददरी खुर्द गांव में वहीं, प्लांट के संचालन में आने के बाद करीब 2,000 लोगों को स्थायी रोजगार उपलब्ध

अदाणी पावर लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 1600 मेगावाट का कोयला आधारित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट निर्माण चरण में प्रवेश कर चुका है। परियोजना को उत्तर प्रदेश सरकार की स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है और इसे न्यूनतम बिडिंग प्रक्रिया के तहत अदाणी समूह को आवंटित किया गया है। हाल ही में नियामक आयोग द्वारा तापीय परियोजना के पावर सप्लाई एग्रीमेंट (पीएसए) को मंजूरी दिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश को 25 वर्षों तक 1500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है। आयोग ने बिजली की दर 5.38 प्रति यूनिट निर्धारित की है, जिससे राज्य को दीर्घकालिक और सुनिश्चित बिजली आपूर्ति मिलने की संभावना है। परियोजना से जुड़े आंकड़ों के अनुसार, निर्माण कार्य के दौरान लगभग 8,000 से 9,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने का अनुमान है। होगा। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक के उपयोग से यह संयंत्र अधिक दक्ष ऊर्जा उत्पादन के साथ अपेक्षाकृत कम उत्सर्जन वाला माना जा रहा है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार, इस परियोजना से क्षेत्र में आधारभूत ढांचे, परिवहन और सहायक उद्योगों के विकास की संभावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। लंबे समय से सीमित औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों की कमी से जूझ रहे इस इलाके में निर्माण कार्य शुरू होने से आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। इसके साथ ही, अदाणी फाउंडेशन द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत मिर्जापुरमें विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। फाउंडेशन के विजन केयर प्रोग्राम के अंतर्गत अब तक 23,000 से अधिक स्कूली बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को नेत्र जांच और उपचार सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

1 से 2 लाख होने में लगे 14 महीने, एक ही महीने में 2 से बढ़कर 3 लाख हुआ भाव

नई दिल्ली, एजेंसी। चांदी की कीमत में जबरदस्त तेजी आई हुई है। पिछले दो कारोबारी दिनों में इसमें करीब 30 हजार रुपये की तेजी आई है। एक दिन पहले ही यानी सोमवार को इसने 3 लाख रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था। एमसीएक्स पर मंगलवार को भी इसमें 7000 रुपये से ज्यादा की तेजी आई। इस तेजी के साथ चांदी की कीमत प्रति किलो 3.17 लाख रुपये से ज्यादा हो गई। इसमें तेजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल यानी 2025 में इसमें करीब 170 प्रतिशत की तेजी आई। इसे दो लाख रुपये से बढ़कर तीन लाख रुपये तक पहुंचने में मात्र एक महीने का ही समय लगा।

चांदी की कीमत पिछले कुछ समय में बहुत तेजी से बढ़ी है। इसे एक लाख से बढ़कर दो लाख रुपये तक पहुंचने में 14 महीने का समय लगा। अक्टूबर 2024 में चांदी की कीमत बढ़कर 1 लाख रुपये प्रति किलो हो गई थी। इसके बाद चांदी में जबरदस्त तेजी आती गई। कई दिन ऐसे रहे जब इसमें लगातार बढ़ोतरी

देखी गई। करीब 12 महीने बाद यानी दिसंबर 2025 में यह बढ़कर प्रति किलो 2 लाख रुपये के आंकड़े पर पहुंच गई।

चांदी को 1 से 2 लाख रुपये तक पहुंचने में बेशक 14 महीने का समय लगा हो, लेकिन 2 लाख से 3 लाख तक पहुंचने में इसे सिर्फ एक महीना ही लगा। एमसीएक्स पर दिसंबर 2025 में चांदी की कीमत 2 लाख रुपये प्रति किलो हो गई थी। वहीं यह कल यानी 19 जनवरी को 3 लाख रुपये के आंकड़े पर पहुंच गई। ऐसे में इसे 2 लाख से 3 लाख रुपये के आंकड़े तक पहुंचने में करीब एक महीने का ही समय लगा। चांदी में तेजी की सबसे बड़ा कारण वैश्विक तनाव और इसकी इंडस्ट्री में बढ़ती डिमांड है। अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापारिक विवाद बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी।

बाजारों में इस बात की भी चर्चा है कि ट्रंप प्रशासन फेडरल रिजर्व के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। अमेरिका द्वारा ब्याज दरों में और कटौती की उम्मीदों के कारण भी चांदी की कीमत में तेजी देखी गई।

आगे गिर सकती है कीमत

चांदी की कीमत में आगे कुछ गिरावट आ सकती है। हाल की एक रिपोर्ट में भविष्यवाणी की गई है कि व्यापारी कुछ मुनाफावसूली और 84 डॉलर प्रति औंस या 2,60,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक की गिरावट देख सकते हैं। इसके बाद कीमतें फिर से बढ़ेंगी। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि तेजी से हो रही वृद्धि से मुनाफावसूली हो सकती है। लेकिन ज्यादातर का मानना है कि आपूर्ति की लगातार चिंताएं और बढ़ती औद्योगिक खपत के बीच कीमती धातुओं का व्यापक दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है।

जियो ने आईपीओ को लेकर बढ़ाया एक और कदम

मुंबई। जियो प्लेटफॉर्म आईपीओ का इंतजार कर रहे निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मॉर्गन स्टेनले और गोल्डमैन सैक्स को प्रस्तावित जियो आईपीओ के लिए लीड बैंकर्स नियुक्त किया गया है। मार्केट के एक्सपर्ट्स का मानना है कि सबसे बड़े टेलीकॉम आईपीओ की वैल्यूएशन 133 बिलियन डॉलर से 182 बिलियन डॉलर रह सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, वित्त मंत्रालय के परमिशन का इंतजार कर रही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से क्लियरेंस मिलने के बाद कंपनी आईपीओ के लिए आवेदन करेगी। आईपीओ में प्राइमरी इश्यू के साथ-साथ सेकेंड्री सेल्स भी किए जाने की संभावना है। केकेआर, टीपीजी, सिल्वर लेकर और विस्ता पार्टनर्स आईपीओ के जरिए अपनी हिस्सेदारी जियो में घटा सकते हैं। वहीं, गूगल (7.75 प्रतिशत) और मेटा (9.99 प्रतिशत) की तरफ से

अपनी हिस्सेदारी को बरकरार रखा जा सकता है। इसके अलावा जियो में 0.7 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले इंटेल की तरफ से भी शेयरों को बेचा जा सकता है। जियो प्लेटफॉर्म ने 2020 में 1.5 लाख करोड़ रुपये कंपनी ने जुटाए थे। इंवेस्टर्स से पैसा जुटाया था। इन पैसों के लिए कंपनी 33 प्रतिशत हिस्से को बेचा था। गूगल (अल्फाबेट) और मेटा प्लेटफॉर्म (पहले फेसबुक) ने इस फंड राउंड के दौरान 7.73 प्रतिशत और 9.99 प्रतिशत को हासिल किया था। दोनों कंपनियों ने क्रमशः 4.5 बिलियन डॉलर और 9.99 बिलियन डॉलर का फंड दिया।

पावर कंपनी अवाना इलेक्ट्रोसिस्टम्स के आईपीओ ने पहले ही दिन किया कमाल

नई दिल्ली, एजेंसी। अवाना इलेक्ट्रोसिस्टम्स के शेयरों ने 20 जनवरी को एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर 77.5 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्टिंग के साथ मजबूत शुरुआत की। यह एसएमई आईपीओ के 59 रुपये प्रति शेयर के भाव से लगभग 31.4 प्रतिशत का प्रीमियम दर्शाता है। मजबूत शुरुआत के बाद, कंपनी के शेयर लगभग 5 प्रतिशत गिरकर 73.65 रुपये प्रति शेयर के निचले सर्किट पर पहुंच गए। शेयर वर्तमान में अपने आईपीओ मूल्य से लगभग 25 प्रतिशत अधिक है। बता दें कि बाजार में इसे लेकर अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा था। लिस्टिंग से पहले कंपनी के आईपीओ को ग्रे मार्केट में करीब 17 प्रतिशत का प्रीमियम मिल रहा था। 35.22 करोड़ के इस एसएमई आईपीओ को निवेशकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। यह इश्यू 14 जनवरी को बंद हुआ था और कुल मिलाकर इसे 131.82 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। सबसे ज्यादा जोश नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स में दिखा, जहां इश्यू 219 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ। वहीं, रिटेल निवेशकों ने अपने हिस्से के शेयरों के लिए 137 गुना से अधिक बोली लगाई। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने भी इसे करीब 55 गुना सब्सक्राइब किया। इससे पहले एंकर निवेशकों ने 9 जनवरी को ही 9.97 करोड़ के शेयर खरीद लिए थे। कंपनी का बिजनेस पावर सेक्टर से जुड़ा हुआ है। कंपनी कस्टमाइज्ड कंट्रोल और रिले पैनल बनाती है, जिनका इस्तेमाल पावर सिस्टम की मॉनिटरिंग, कंट्रोल और प्रोटेक्शन में किया जाता है। इसके प्रोडक्ट्स ट्रांसमिशन लाइन, पावर ट्रांसफॉर्मर, सबस्टेशन और बस बार जैसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल होते हैं। कंपनी 11 केवी से लेकर 220 केवी तक के वोल्टेज से जुड़े पैनल और रिले बनाती है। अवाना इलेक्ट्रोसिस्टम्स की दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बेंगलुरु के पीण्या इंडस्ट्रियल एरिया में हैं और फिलहाल कंपनी में 129 कर्मचारी काम कर रहे हैं।

6 जनवरी से हर रोज लग रहा था लोअर सर्किट

गिरते बाजार में लगने लगा अपर सर्किट

मुंबई, एजेंसी। आज हम ऐसे मल्टीबैगर स्मॉल-कैप स्टॉक की बात कर रहे हैं, जिसमें बीते छह जनवरी से हर रोज लोअर सर्किट लग रहा था। लेकिन कल और आज, दोनों दिन, अपर सर्किट लगा है। यह शेयर है.-1 लिमिटेड का शेयर। हालांकि कल भी शेयर बाजार में गिरावट थी और आज भी सुबह से ही बाजार गिरा हुआ है।

ए-1 लिमिटेड (बीएसई - 542012) ने कल ही एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि इसकी सहयोगी कंपनी और समूह की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पहल का हिस्सा ए-1 सुरेजा इंडस्ट्रीज को लो-स्पीड वाले इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की सप्लाई के लिए कुल 1,425 यूनिट के दो परचेज आर्डर मिले हैं। पहला परचेज आर्डर 12 जनवरी 2026 को अहमदाबाद (गुजरात) स्थित जिपनोवा एंटरप्राइज एलएलपी से मिला है। इसके तहत 525 स्लो-स्पीड ई टू-व्हीलर की सप्लाई के लिए है। दूसरा आर्डर 14 जनवरी 2026 को नोएडा (उत्तर प्रदेश) स्थित आयुष्मान इंजीनियरिंग द्वारा 900 स्लो-स्पीड ई टू-व्हीलर के लिए मिला है। इसके शेयर में बीते छह जनवरी से लगातार लोअर सर्किट लग रहा था। इस तरह से यह 16 जनवरी को 32 रुपये तक आ गया था। लेकिन कल यानी 19 जनवरी को यह खबर आते ही इसके शेयर सीधे 5 फीसदी का छलांग लगाते हुए

33.6 रुपये पर पहुंच गया। आज भी यह सुबह ही 1.60 रुपये की बढ़त के साथ अपर सर्किट में पहुंच गया। इसमें पांच फीसदी का अपर सर्किट है।

इस स्मॉल-कैप मल्टीबैगर स्टॉक में पिछले दिनों गिरावट देखी गई। पिछले सप्ताह बीते पांच सत्र के दौरान यह 10 फीसदी से ज्यादा और एक महीने में 24 फीसदी लुढ़क गया है। लेकिन यदि ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में देखें तो इसने छह महीने में ही 106.13 फीसदी का रिटर्न और एक साल में 219.39 फीसदी का रिटर्न दिया है। बीते पांच साल में यह शेयर 2185.71 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। ए-1 लिमिटेड ने हाल ही में शेयरधारकों को 3:1 अनुपात में बोनस शेयर दिया है। इसके तहत शेयरधारकों को हर 10 रुपये के पूर्ण भुगतान वाले इक्विटी शेयर के बदले 10 रुपये के तीन बोनस इक्विटी शेयर जारी किए गए थे। इससे पहले 10 रुपय वाले शेयरों को 1 रुपये के पूर्ण भुगतान वाले 10 इक्विटी शेयरों में उप-विभाजित करने की प्रक्रिया भी पूरी की गई थी। इस कदम का उद्देश्य बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाना और शेयरधारकों को पुरस्कृत करना था।

शहरी सहकारी बैंकों को आरबीआई गवर्नर की दो टूक

गवर्नेंस, एसेट क्वालिटी से समझौता मंजूर नहीं

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शहरी सहकारी बैंकों (अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक या यूसीबी) को साफ कर दिया कि सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को अपनी साख बनाए रखने के लिए गवर्नेंस के उच्च मानकों का पालन करना होगा। केंद्रीय बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सोमवार को ऐसे बैंकों को विशेष रूप से एसेट क्वालिटी पर कड़ी निगरानी रखने और मजबूत अंडरराइटिंग प्रथाओं को अपनाने की वकालत की है। यह निर्देश मुंबई में आयोजित एक उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान दिया गया, जहां गवर्नर चुनिंदा यूसीबी के चेयरपर्सन, प्रबंध निदेशकों (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) को संबोधित कर रहे थे।

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बैठक में साफ किया कि यूसीबी को केवल कर्ज बांटने तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि उस कर्ज की गुणवत्ता सुनिश्चित करना भी उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने एसेट क्वालिटी पर मेहनती निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया। बैंकिंग सेक्टर में बढ़ते जोखिमों के बीच गवर्नर का यह बयान महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मजबूत अंडरराइटिंग प्रथाओं को अपनाना समय की मांग है, ताकि बैड लोन या एनपीए जैसी समस्याओं से बचा जा सके।

सहकारी बैंकों की प्रासंगिकता पर बात करते हुए गवर्नर ने कहा कि क्रेडिट डिलीवरी यानी ऋण वितरण में यूसीबी की भूमिका अहम बनी हुई है। विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह नहीं पहुंची हैं, वहां वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में ये बैंक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। गवर्नर ने भरोसा जताया कि रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में शुरू की गई नीतिगत पहल इस क्षेत्र को मजबूत बनाने और स्वस्थ तरीके से विकसित होने में मदद करेंगी। बैंकिंग व्यवसाय पूरी तरह से भरोसे पर टिका है। गवर्नर मल्होत्रा ने बैंकरों को ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि क्षेत्र में ग्राहकों का विश्वास बनाए रखने के लिए नैतिक प्रथाओं का

पालन करना और समय पर शिकायतों का निवारण करना अनिवार्य है। इस इंटरैक्टिव सत्र के दौरान, यूसीबी के प्रमुखों ने नीतिगत मुद्दों और परिचालन मामलों पर अपने सुझाव और फीडबैक साझा किए। बैठक में नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनयूसीएफडीसी) और नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड (एनएएफसीयूबी) के प्रतिनिधि भी शामिल थे।

बैठक में गवर्नर के अलावा डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे और एससी मुर्मू भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि इस तरह की पिछली बैठक पिछले साल मार्च में आयोजित की गई थी। आरबीआई का यह कदम बताता है कि रेगुलेटर सहकारी बैंकों को मुख्यधारा की बैंकिंग प्रणाली के समकक्ष और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए गंभीर है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शहरी सहकारी बैंकों को गवर्नेंस और एसेट क्वालिटी सुधारने के निर्देश दिए। जानें मुंबई बैठक में ग्राहकों के भरोसे और अंडरराइटिंग पर क्या कहा गया।

रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर सिंह ब्रदर्स में मची है रार?

500 करोड़ रुपये का है मामला

नई दिल्ली, एजेंसी। देश की प्रमुख फार्मा कंपनी रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर्स भाई शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह एक बार फिर से आमने-सामने आ गए हैं। मामला फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजन ढाल चैरिटेबल सोसायटी का है। एक समय भारत की हेल्थकेयर इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमा चुके दोनों भाई के झगड़े अब आम हो गए हैं। साल 2019 में दोनों भाइयों को जापानी कंपनी दाइची सांक्यो केस में अवमानना का दोषी पाया गया था। दवा बनाने वाली दाइची सांक्यो ने 3500 करोड़ रुपये नहीं चुकाने पर सिंह बंधुओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

इस बार दोनों भाइयों के बीच राजन ढाल चैरिटेबल सोसायटी को लेकर रार मची है। मालविंदर की पत्नी जापना सिंह का आरोप है कि शिविंदर और उनकी पत्नी

अदिति ने फर्जीवाड़ा कर उन्हें और अन्य मेंबर्स को सोसायटी से बाहर कर दिया है। इसके जरिए 500 करोड़ रुपये के वसंत कुंज स्थित फोर्टिस राजन ढाल अस्पताल और उसके सालाना 30 करोड़ रुपये के रेवेन्यू पर कब्जा कर लिया है। आज शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह बेशक आमने-सामने हों, लेकिन एक समय दोनों भाइयों की देश के हेल्थकेयर सिस्टम पर मजबूत पकड़ थी।

साल 1937 में रणबीर और गुरबक्स नाम के दो चचेरे भाइयों ने मिलकर दवाओं के डिस्ट्रिब्यूशन की एक कंपनी की शुरुआत की। रणबीर के नाम का शुरुआती अक्षर और गुरबक्स के नाम के आखिरी अक्षरों को मिलाकर इसका नाम रैनबैक्सी पड़ा। साल 1952 में उन्होंने यह कंपनी भाई मोहन सिंह को बेच दी। उनके बाद उनके बेटे परविंदर सिंह ने कंपनी की कमान संभाली और इसने खूब तरक्की की। साल 2000 में परविंदर सिंह के निधन के बाद उनके दोनों बेटे मालविंदर और शिविंदर ने कंपनी का जिम्मा संभाल लिया। मालविंदर सिंह और शिविंदर सिंह रैनबैक्सी, फोर्टिस हेल्थकेयर और रेलिगेयर इंटरप्राइजेज के मालिक रह चुके हैं। बाद में दोनों भाइयों को वक्त ने ऐसी चोट दी की वे दिवालिया हो गए। साल 2008 में उन्होंने रैनबैक्सी में अपनी हिस्सेदारी जापान की कंपनी दाइची सांक्यो को 9576 करोड़ रुपये में बेच दी। इससे मिले पैसों में से उन्होंने साल 2009-10 में 2,000 करोड़ रुपये कर्ज और टैक्स चुकाने में खर्च किए। वहीं 1,700 करोड़ रुपये अपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी रेलिगेयर में और 2,230 करोड़ रुपये अपने हॉस्पिटल चेन फोर्टिस में निवेश किया। बाद में मंदी के कारण उन्हें काफी घाटा हुआ। कर्ज भी हो गया। अप्रैल 2010 में दोनों भाइयों को रेलिगेयर के बोर्ड से निकाल दिया गया। साल 2012 में दाइची ने सिंगापुर के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में की गई।

लगातार 10वें दिन भी गिरा ओला का शेयर

नई दिल्ली, एजेंसी। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक के शेयर मंगलवार, 20 जनवरी को लगातार 10वें सत्र में भी गिरावट है। मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) हरीश अबिचंदानी के इस्तीफे के बाद शेयर में एक और 5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई और यह 33.82 रुपये पर आ गया। इस 10-दिवसीय मंदी के दौरान शेयर ने लगभग 22 प्रतिशत की कमी दर्ज की है। ओला ने सोमवार को एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि हरीश अबिचंदानी ने 19 जनवरी, 2026 की शाम से कंपनी के सीएफओ पद से इस्तीफे दे दिया है। अबिचंदानी ने अपने इस्तीफे के पीछे निजी कारण बताए हैं। साथ ही, बोर्ड ने दीपक रस्तोगी की नियुक्ति सीएफओ के रूप में मंजूर की है, जो 20 जनवरी, 2026 से प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और वरिष्ठ प्रबंधन टीम का हिस्सा भी होंगे। रस्तोगी इससे पहले प्रॉपर्टी डेवलपर पुरवंकरा के ग्रुप फाइनेंस चीफ थे। इससे पहले दिसंबर में, ओला में वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक और बिजनेस हेड - सेल, विशाल चतुर्वेदी ने भी निजी प्रतिबद्धताओं के कारण अपना इस्तीफा दे दिया था। इस साल के पहले तीन ट्रेडिंग सेशन को छोड़कर, ओला इलेक्ट्रिक का शेयर जनवरी के अन्य सभी सत्रों में नीचे रहा है, जिससे इसमें 6 प्रतिशत की मासिक गिरावट दर्ज हुई है। यह ईवी निर्माता कंपनी के लिए लगातार चौथा मासिक नुकसान है, जो 2024 में अपने शेयर बाजार में एंट्री के बाद से अधिकांश समय से गिरावट के दौर में है।

COURT NOTICE
(U/o 5 Rule 20 CPC)
(SUCCESSION CASE)
IN THE COURT OF
Sh. Sachin Yadav
Addl. Civil Judge (Sr. Division), Chandigarh
JATINDER NATH
Vs
GENERAL PUBLIC
CNR No. CHCH02-005380-2025
Next Date: 25.02.2026
NOTICE TO:
GENERAL PUBLIC
In above titled case, the defendant(s)/ respondent(s) could not be served. It is ordered that defendant(s)/respondent(s) should appear in person or through counsel on 25.02.2026 at 10.00 a.m.
For details logon to http://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice & district=Chandigrah.
Sachin Yadav
Addl. Civil Judge (Sr. Division), Chandigarh
Dated, this day of 02.01.2026

जमी नदी में मछलियां पकड़ रहे हज़ारों लोग, तीन साल बाद दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ फेस्टिवल

दक्षिण कोरिया में आइस फे स्टिवल शुरू हुआ है यह वास्तव में मछली पकड़ने का फे स्टिवल है, जो कि दक्षिण कोरिया के गंगवान प्रांत की नदी पर हो रहा है।

यह नदी भीषण सर्दी से पूरी तरह जम चुकी है। नदी की ऊपरी सतह पर 6 इंच मोटी बर्फ की परत जम गई है। जनवरी में इस इलाके का तापमान माइन 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इस फेस्टिवल में हज़ारों लोग हिस्सा ले रहे हैं। इस फेस्टिवल के दौरान लोग नदी पर जमी बर्फ में छेद करते हैं। फिर हाथ या कांटे से मछली पकड़ते हैं।

क्या है दशकों पुराना केसलर सिंड्रोम

स्पेस से क्या है इसका कनेक्शन?

अंतरिक्ष में बढ़ता कचरा किसलर सिंड्रोम पैदा करने के हालात बना रहा है. अंतरिक्ष में बढ़ता कचरा किसलर सिंड्रोम पैदा करने के हालात बना रहा है. स्पेस में कचरे के कारण पैदा होने वाली समस्या का अनुमान दशकों पहले ही लगा लिया गया था. नासा के एक वैज्ञानिक ने इससे पैदा होने वाले एक चरम हालात को एक सिंड्रोम की तरह परिभाषित किया था. वैज्ञानिक मानते हैं कि आज पृथ्वी की निचली कक्षा इस स्थिति के शुरुआती चरण में पहुंच चुकी है.

स्पेस बहुत बड़ा इलाका है और यहां तक कि पृथ्वी की निचली कक्षा भी. हम अब तक हजारों सैटेलाइट स्पेस में भेज चुके हैं और उनमें से बहुत से खराब होकर वहीं रह गए हैं और वे और उनके टुकड़े कचरे के तौर पर वहीं रह कर पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं. पर क्या यह कचरा दूसरे सैटेलाइट्स के लिए खतरा है? हां बिलकुल पर कितना बड़ा? यह बहस का विषय है. लेकिन उतनी ही चिंता का भी. हमारे वैज्ञानिकों ने दशकों पहले इस खतरे को लेकर चेताना शुरू कर दिया था और यहीं केसलर सिंड्रोम का नाम आता है. आइए जानते हैं कि यह केसलर सिंड्रोम क्या है और इसका इस कचरे से क्या संबंध है?

क्या है केसलर सिंड्रोम

अंतरिक्ष के खतरे को 1970 के दशक से ही पहचान लिया गया था. नासा के वैज्ञानिक डोनाल्ड केसलर ने 1978 में एक काल्पनिक स्थिति का प्रस्ताव दिया था जो भविष्य में कभी ना कभी जरूर आ सकती थी. और अब यह जल्दी ही आ जाएगी ऐसा माना जाने लगा है. इस स्थिति में पृथ्वी की निचली कक्षा में टकराव की घटनाएं शुरू हो जाएंगी जिसमें सैटेलाइट, अंतरिक्ष यान, रॉकेट आदि टकराकर टूटेंगे और ज्यादा कचरा पैदा कर टकरावों की घटनाओं का ऐसा सिलसिला चला देंगें जो कभी खत्म ही नहीं होगा. इसके बाद हालात ऐसे हो जाएंगी कि कक्षा में कचरा इतना भर जाएगा, भावी पीढ़ी के लिए उसका इस्तेमाल संभव ही नहीं रह जाएगा.

क्या होगा इससे

इसका सबसे बड़ा नतीजा यही होगा कि वो सारी तकनीकें जिनका आज हम स्पेस टेक्नोलॉजी के कारण उपयोग कर पा रहे हैं, वे खत्म हो जाएंगी. इनमें जीपीएस, सैटेलाइट कम्यूनिकेशन, मौसम निगरानी, और यहां तक कि अंतरिक्ष अनुसंधान तक पर बहुत बुरा असर पड़ेगा. ये हालात कितने भी काल्पनिक हों, लेकिन इनका खतरा और जोखिम बढ़ रहा है. और अभी तो तेजी से हजारों सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च होने वाले हैं. इन्हें रोकना नामुमकिन है. अगर जल्दी ही समाधान नहीं निकला तो पृथ्वी की कक्षा उपयोग के लायक ही नहीं रह जाएगी.

क्या क्या होगा इस कचरे में?

स्पेस डेबरी या स्पेस जंक में बहुत कुछ आता है. इसमें खत्म हो चुके सारे सैटेलाइट, इंसानों का छोड़ गया कचरा, रॉकेट के वे हिस्से जो पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं जा पाए हैं, बेकार हो चुके अंतरिक्ष यान और उन सबके टूट चुके टुकड़े शामिल हैं. यूरोपीय स्पेस एजेंसी के मुताबिक, 1950 से करीब 50 हजार टन का पदार्थ स्पेस में लॉन्च किया जा चुका है और सितंबर 2025 तक 13 हजार टन का सामान कक्षा में ही पड़ा है. अब तक लॉन्च किए गए 19590 सैलेटलाइट में से 13230 अब भी कक्षा में हैं और इनमें से 10200 फिलहाल काम कर रहे है.

एक इंच का कचरा भी तबाही के लिए काफी

परेशानी ये है कि एक इंच का कचरा भी हजारों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कक्षा में घूमता है और वह एक स्पेस स्टेशन से टकरा कर उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए काफी होता है. ऐसी घटना से बचने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कई बार अपनी स्थिति बदलनी पड़ी है. ऐसा लगभग सभी सैटेलाइट करते ही रहते हैं.

साफ कैसे होगा ये कचरा?

साफ है कि केसलर सिंड्रोम के हालात बनने से पहले ही स्थिति से निपटने के तरीके खोजने होंगे और समाधान खोज कर समस्या का हल निकालना होगा. इस कचरे को साफ करने के लिए कई तरह की रिसर्च चल रही हैं. इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का सुझाव है कि हर कंपनी को उसके सैटेलाइट के 25 साल पूरे करने के बाद उसके कचरे को खुद ही हटाना होगा. वहीं निजी कंपनियां इसमें व्यवसाय की संभावनाएं देख कई सुझावों के साथ आगे आई हैं. पर सबसे बड़ी चुनौती उपायों को लागू कर उनका नियमन होगा

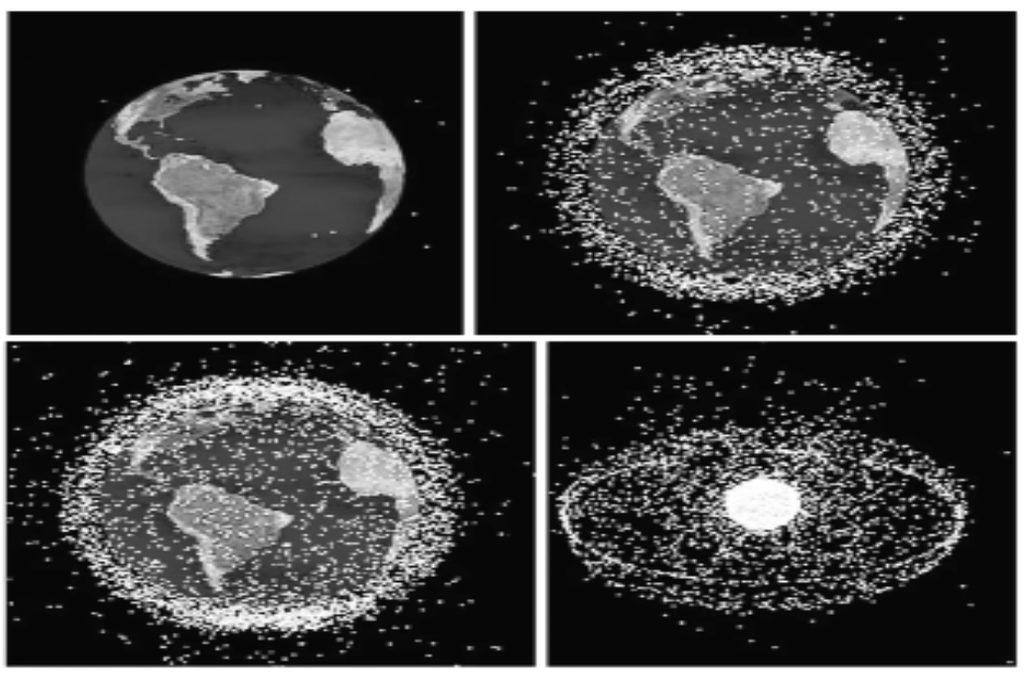

दुनिया का सबसे बड़ा आइस फेस्टिवल है हार्बिन इंटरनेशनल स्नो फेस्टिवल

हार्बिन इंटरनेशनल आइस एंड स्नो फेस्टिवल, चीन के हार्बिन शहर में हर साल जनवरी से फरवरी के अंत तक आयोजित किया जाता है. यह दुनिया का सबसे बड़ा आइस फेस्टिवल है. यह फेस्टिवल करीब एक महीने तक चलता है. इस फेस्टिवल में बर्फ से बनी कलाकृतियां बनाई जाती हैं. हर साल एक थीम के साथ यह फेस्टिवल मनाया जाता है. इस फेस्टिवल में 12 देशों के कलाकार हिस्सा लेते हैं. हार्बिन इंटरनेशनल आइस एंड स्नो फेस्टिवल की शुरुआत 1985 में की गई थी। हार्बिन चीनी भाषा का शब्द है। जिसका शाब्दिक अर्थ वह जगह जहां मछलियों को पकड़ने वाला जाल सुखाया जाता है।

चीन केहेलोंगजियांग प्रांत में होने वाला हर्बिन आइस फेस्टिवल दुनियाभर में बर्फ की सबसे बड़ी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। इस फेस्ट में बर्फ से न केवल मूर्तियां आदि बनाई जाती हैं, बल्कि बर्फ से महल यहां तक की पूरा ड्रीम वर्ल्ड बनाया जा चुका है। सोमवार को आइस एंड स्नो वर्ल्ड को ट्रायल के लिए खोला गया, जिसमें बर्फ से बनी कलाकृतियों को रंग बिरंगी रोशनियां डालकर सजाया गया था। हर्बिन शहर में पड़ने वाली जबरदस्त बर्फ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन यहां हर्बिन आइस फेस्टिवल का आयोजन करता है। फेस्टिवल में आइस एंड स्नो वर्ल्ड, आर्ट एंड स्नो आर्ट एग्जीबिशन, आइस लेंटर्न आर्ट फेयर, विंटर स्वीमिंग, आइस होटल, स्कीइंग और स्लेज जैसे कई आकर्षण है। इस फेस्ट की गिनती दुनिया के सबसे बड़े स्नो फेस्ट में होती है। हर साल इस बर्फीली दुनिया को देखने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा लोग आते हैं।

हाड़ कंपा देने वाली ठंड में चीन में लगने वाला स्नो वर्ल्ड पार्क खुल गया है। -20 डिग्री तापमान में 2000 कलाकारों ने बर्फ से बनी कलाकृतियां बनाई हैं। इन कलाकारों ने दिन रात मेहनत कर इस अनोखी कलाकृतियों को बनाया है। हर साल चीन के हेइलोंगजियांग प्रांत के हार्बिन शहर में बर्फ से बनी कलाकृतियों का आइस एंड स्नो वर्ल्ड का आयोजन किया जाता है। यह फेस्ट दो महीने तक चलेगा और यह विश्व का अपनी तरह का इकलौता पार्क है। यह उत्सव फरवरी के आखिर तक चलेगा। इस सलाना उत्सव में न सिर्फ चीन के लोग बल्कि दुनियाभर के पर्यटक इस फोजन सिटी आते हैं और बर्फ की बनी कलाकृतियों का आनंद लेते हैं।

यह पूरा पार्क छह लाख वर्ग मीटर में फैला है इसलिए इसे स्नो वर्ल्ड भी कहते हैं। इस पार्क में अपनी कला का जलवा दिखाने देश-विदेश के कलाकार भाग लेते हैं। बता दें कि हेइलोंगजियांग प्रांत काफी ठंडा है। हर साल इसकी प्रसिद्धी को देखते हुए इसका फेस्टिवल का आकार प्रकार बड़ा होता जा रहा है। पिछले साल यह पार्क 8 लाख वर्ग मीटर में बनाया गया था, जिसमें 1.5 लाख घन मीटर बर्फ उपयोग की गई थी। यह बर्फ 2023 की तुलना में 30 हजार घन मीटर अधिक उपयोग की गई थी। पार्क में स्कल्पचर बनाने में 1.8 लाख बर्फ के क्यूब का इस्तेमाल हुआ था। बता दें कि यह फेस्टिवल करीब 35 साल से आयोजित किया जा रहा है और इसे देखने हर दिन करीब एक लाख से अधिक लोग आते हैं। इन अजूबों को चीन और दुनियाभर के 12 देशों से पहुंचे 10 हजार कलाकारों ने बनाया है, वह भी बर्फ में माइनस 10 से माइनस 20 डिग्री तापमान के बीच। हर साल दिसंबर के वक्त तापमान काफी नीचे गिर जाता है। शिन्हुआ न्यूज एजेंसी के मुताबिक, शहर के एयरपोर्ट पर 2025 में दो करोड़ से ज्यादा यात्री आए। पर्यटकों के बीच हार्बिन में बना साइबेरियन टाइगर पार्क भी लोकप्रिय है। यहां एक हजार से ज्यादा साइबेरियाई टाइगरों को ठंडे पर्यावरण के बीच सुरक्षित माहौल में रखा गया है।

बर्फ की मूर्तियों के अलावा, यहाँ अन्य गतिविधियां भी होती हैं। इसमें सर्दियों में होने वाली तैराकी, बर्फ बोटिंग के साथ-साथ बर्फ पर होने वाला सामूहिक विवाह समारोह भी शामिल है। यहां दुनिया भर से लोग शादी करने पहुंचते हैं।

क्या आपको पता है पुलिस का फुल फॉर्म?

पुलिस ये एक ऐसा शब्द है, जिससे है व्यक्ति अपने बचपन से ही परिचित होता है। सभी जानते हैं कि देश के किसी भी क्षेत्र में होने वाले अपराधों से निपटने में पुलिस अहम भूमिका निभाती है और सुरक्षित समाज के निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा साबित होती है। पुलिस के कर्तव्यों और उनसे मिलने वाली मदद से तो लगभग हर कोई परिचित है लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाकी पदों की तरह आखिर पुलिस का फुल फॉर्म क्या होता है। जाहिर सी बात है बहुत कम लोगों को इस बारे में जानकारी होगी।

सुरक्षित समाज की निर्माता

पुलिस एक ऐसा सुरक्षा बल है, जो देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर पल डटकर खड़ा रहता है। जिस तरह से सेना देश की सीमा पर खड़े होकर बाहरी दुश्मनों से हमारी रक्षा करती है। ठीक उसी तरह से आंतरिक क्षेत्र में मौजूद अनैतिक गतिविधियों से निपटकर, अपराधियों को पकड़ कर समाज और लोगों की रक्षा करती है।

सितारे दर्शाते हैं पद

पुलिस में महिला और पुरुषों दोनों की ही भर्ती होती है जिन्हें आरक्षी और आरक्षक कहा जाता है। पद के हिसाब से वर्दी पर सितारे अंकित किए जाते हैं। जो ये दर्शाते हैं कि किस पुलिस अधिकारी के पास विभाग का कौन सा पद है। पुलिस विभाग में कार्यरत कांस्टेबल से लेकर उच्च श्रेणी तक के सभी अधिकारियों का काम देश की आंतरिक सुरक्षा होता है।

जनता की सहायक

पुलिस विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को देश की सुरक्षा और कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार होता है। देश की कानून व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखना और किसी मामले में परेशान व्यक्ति की मदद करना पुलिस का मुख्य काम है और कोई भी इनसे मदद ले सकता है। किसी भी समस्या से परेशान चल रहा व्यक्ति अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पर जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है।

पुलिस का पूरा नाम

भारत में पुलिस विभाग की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा की गई थी और उसके बाद से आज तक यह देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था का प्रमुख अंग है। पुलिस का फुल फॉर्म पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसी होता है। नाम से ही जाहिर है कि ये सुरक्षा बल जनता की सहायता के लिए काम करता है।

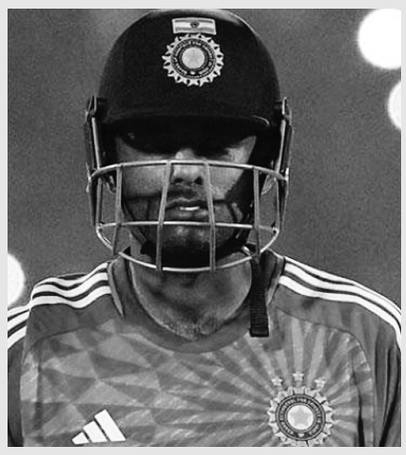

आज टी-20 मैच में सूर्यकुमार पर रहेगी निगाहें, 25 रन बनाते ही नाम होगा ये रिकॉर्ड

नागपुर (एजेंसी)। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का आगाज 21 जनवरी से नागपुर में होने जा रहा है। यह सीरीज सिर्फ टीम इंडिया के संयोजन के लिहाज से नहीं, बल्कि कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए भी बेहद अहम मानी जा रही है। लंबे समय से टी20 फॉर्मेट में रन बनाने के लिए जूझ रहे सूर्यकुमार के सामने खुद को साबित करने का सुनहरा मौका होगा। फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि क्या 'मिस्टर 360 डिग्री' एक बड़ी पारी के साथ वापसी कर पाएंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में सूर्यकुमार यादव एक बड़े व्यक्तिगत मुकाम को छू सकते हैं। वह टी20 क्रिकेट में 9000 रन पूरे करने से महज 25 रन दूर हैं। ऐसा करने पर वह इस आंकड़े तक पहुंचने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे। उनसे पहले विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। पिछले एक साल में सूर्यकुमार यादव का टी20 प्रदर्शन उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं रहा है। विस्फोटक बल्लेबाज के तौर पर पहचान बनाने वाले सूर्या लगातार अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहे हैं। कई क्रिकेट जानकारों का मानना है कि अगर वह टीम के कप्तान नहीं होते, तो टी20 वर्ल्ड कप की संभावित योजनाओं में उनका नाम संदिग्ध हो सकता था। हालांकि टीम मैनेजमेंट और सीनियर खिलाड़ियों ने उन पर भरोसा जताया है।

3 साल से कोर्ट से दूर साइना नेहवाल का संन्यास

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने प्रोफेशनल बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया कि घुटने के दर्द के कारण अब उनके लिए खेलना संभव नहीं रह गया है। साइना आखिरी बार जून 2023 में सिंगापुर ओपन में खेली थीं।35 वर्ष की साइना ने एक पॉडकास्ट में कहा, मैंने दो साल पहले ही खेलना बंद कर दिया था। मैंने अपनी शर्तों पर खेलना शुरू किया और अपनी शर्तों पर ही छोड़ा। इसलिए मुझे घोषणा जरूरी नहीं लगी। पूर्व वर्ल्ड नंबर-1 साइना ने लंदन ओलिंपिक-2012 में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। वे ओलिंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उन्होंने 3 ओलिंपिक गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया। साइना ने 2008 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीतकर पहली बार सुर्खियां बटोरी थीं। वे 2009 में बीडब्ल्यूएफ सुपर सीरीज प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय बनीं। इसके बाद 2010 और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीते।साइना के मुताबिक उनके घुटनों का कार्टिलेज पूरी तरह घिस चुका है और उन्हें आर्थराइटिस हो गया है। उन्होंने कहा, जब आप खेल ही नहीं पा रहे तो वहीं रुक जाना चाहिए। मैं पहले दिन में 8-9 घंटे ट्रेनिंग करती थी, लेकिन अब मेरे घुटने 1-2 घंटे में ही जवाब दे देते हैं। इसके बाद सूजन आ जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि अब बहुत हो गया। मैं अब अपना करियर और नहीं खींच सकती।

विराट और रोहित शर्मा का हो सकता है 'डिमोशन'!

ए+ कैटेगरी खत्म करने की तैयारी कर रहा बीसीसीआई

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अपने वार्षिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी में है। न्यूज एजेंसी एएनआई के विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक, मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट संरचना में सबसे प्रीमियम ए+ कैटेगरी को स्क्रैप यानी हटाने/बंद करने करने का प्रस्ताव है। यदि ऐसा होता है, तो भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गज, विराट कोहली और रोहित शर्मा नए मॉडल में 'ग्रेड बी' में रखे जा सकते हैं। चयन समिति, जिसका नेतृत्व पूर्व क्रिकेटर अजीत अगरकर कर रहे हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर को सरल और प्रैक्टिकल बनाने की दिशा में बदलाव सुझाए हैं।

ए+ कैटेगरी हटेगी

केवल 3 कैटेगरी होंगी- ए, बी या सी ए+ कैटेगरी में आने वाले खिलाड़ियों की वार्षिक सैलरी अभी सात करोड़ रुपये है। इसे हटाकर संरचना को अधिक परफॉर्मेंस-आधारित बनाने की कोशिश मानी जा रही है। अगली अपेक्स काउंसिल मीटिंग में इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लग सकती है। कोहली और रोहित सिर्फ वनडे पर फोकस करते हैं। टी20 अंतरराष्ट्रीय से दोनों 2024 में संन्यास ले चुके हैं। टेस्ट से भी दोनों ने पिछले साल संन्यास ले लिया था।

अभी की कॉन्ट्रैक्ट संरचना कैसी है?

ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ खिलाड़ियों को एक साल का वेतन देने का जरिया नहीं हैं, बल्कि यह बीसीसीआई का एक सुव्यवस्थित मॉडल है जिसके जरिए प्रदर्शन, निरंतरता, क्रिकेट के अलग-अलग प्रारूपों में योगदान और चयनकर्ताओं के मूल्यांकन के आधार पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में बीसीसीआई ने कई चौंकाने वाले फैसले भी लिए, जिसकी कभी सराहना हुई तो कभी आलोचना झेलनी पड़ी। केंद्रीय अनुबंध में जगह बनाने के लिए बीसीसीआई ने पिछले चक्र में कुछ बदलाव भी किए थे। बीसीसीआई ने जब साल 2024-2025 के लिए खिलाड़ियों के वार्षिक अनुबंध की सूची का एलान किया था, तो उस लिस्ट में कुल 34 खिलाड़ी थे। चार खिलाड़ियों को ए+ ग्रेड में रखा गया था। वहीं, छह खिलाड़ियों को ए ग्रेड में रखा गया था। पांच खिलाड़ी बी ग्रेड और 19 खिलाड़ी सी ग्रेड में थे।

तीन मैच बदल देंगे श्रेयस की तकदीर!

टी20 में वापसी तो हुई, पर क्या विश्वकप टीम में जगह बना पाएंगे!

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय वनडे उप-कप्तान श्रेयस अय्यर ने फिर से टी20 टीम में जगह बना ली है। चयनकर्ताओं ने उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ 21, 23 और 25 जनवरी को होने वाले तीन टी20 मैचों के लिए टीम में शामिल किया है। वह तिलक वर्मा की जगह टीम में आए हैं, जो फिलहाल चोट से जूझ रहे हैं। वापसी का यह समय बेहद अहम है, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप में अब एक कुछ ही दिनों का समय बचा है। चोटें और फॉर्म किसी भी बड़े टूर्नामेंट का समीकरण बदल सकती हैं, इसलिए चयनकर्ता अनुभवी विकल्पों को तैयार रख रहे हैं।श्रेयस का यह पहला टी20 कॉल-अप 2023 में ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद आया है। 2024 वर्ल्ड कप से ठीक पहले उन्हें ड्रॉप किया गया था, जो उनके लिए बड़ा झटका था। इसके बाद उन्होंने आईपीएल में करियर की नई ऊंचाइयाँ छुईं। 2024 में उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाया और 2025 में पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाया। व्यक्तिगत तौर पर, आईपीएल 2025 उनका सुनहरा सीजन रहा।

श्रेयस ने 604 रन बनाए और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 175 और औसत 50.33 का रहा। इस दौरान उन्होंने छह अर्धशतक लगाए। श्रेयस ने 43 चौके और 39 छक्के जड़े। सबसे खास बात यह रही कि धीमी पिचों पर स्पिन पर उनकी पकड़ मजबूत दिखी। कोच राहुल द्रविड़ ने कुछ साल पहले श्रेयस के स्वभाव पर कहा था, 'उनकी सबसे बड़ी खासियत उनका टेम्परामेंट है। दबाव में भी वो खुद को बेहतर तरीके से संभालते हैं।' यह बयान आज भी उनके करियर के साथ फिट बैठता है।

भारतीय टी20 टीम में बढ़ी भीड़: जगह मिलेगी कैसे

2024 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत की टी20 टीम का स्तर और चयन दोनों बदला है। लगातार सीरीज जीत, नई प्लेइंग कॉम्बिनेशन और प्रदर्शन की निरंतरता ने जगह पाना और मुश्किल बना दिया है। ईशान किशन, रिंकू सिंह, शिवम दूबे और संजू सैमसन जैसे बल्लेबाज जगह के लिए पहले से ही कतार में हैं। ऐसे में अय्यर को सीमित मौकों में तुरंत बड़ा प्रभाव दिखाना होगा।

टीम इंडिया के लिए राहत की खबर

सर्जरी के बाद स्टार बल्लेबाज तिलक ने शुरू की ट्रेनिंग

नई दिल्ली, एजेंसी। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर सामने आई है। स्टार टी20 बल्लेबाज और टीम के डिज़ाइनेटेड नंबर-3 तिलक वर्मा ने सर्जरी के बाद फिजिकल ट्रेनिंग दोबारा शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, तिलक जल्द ही भारत के लिए मैदान पर वापसी कर सकते हैं और उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के आखिरी दो टी20 मुकाबलों के लिए टीम में शामिल किया गया है। तिलक वर्मा को विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के दौरान टेस्टिकुलर टॉर्शन की समस्या के चलते सर्जरी करानी पड़ी थी। इसी कारण वह न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20द्ध सीरीज के पहले तीन मुकाबलों से बाहर हो गए थे।अब, टी20 वर्ल्ड कप में दो हफ्ते से थोड़ा ज्यादा समय बाकी है और तिलक ने वापसी की दिशा में बड़ा कदम उठा लिया है।

चौथे T20 में वापसी का लक्ष्य

एक सूत्र के अनुसार, 'अगर सब कुछ ठीक रहा तो तिलक 28 जनवरी को विशाखापट्टनम में होने वाले चौथे टी20 से पहले पूरी तरह फिट हो जाएंगे। उन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग शुरू कर दी है और एक-दो दिन में बल्लेबाज़ी और अन्य स्किल-बेस्ड ट्रेनिंग भी शुरू कर देंगे।' फिलहाल बल्लेबाज़ी शुरू नहीं, दर्द भी नहीं रिपोर्ट में बताया गया है कि तिलक फिलहाल बल्लेबाज़ी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी तरह का दर्द महसूस नहीं हो रहा है। वह जल्द ही बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचेंगे, जहां फिटनेस टेस्ट के बाद उन्हें रिटर्न टू प्ले की हरी झंडी दी जाएगी। तिलक वर्मा की अनुपस्थिति में श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल किया गया।

भारतीय एथलीट्स के साथ दुर्व्यवहार, ट्रेन से जबरन उतारने से मचा बवाल

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत के शीर्ष पोल वॉल्टर्स, राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी देव मीना और विश्वविद्यालय चैंपियन कुलदीप यादव सोमवार को एक ट्रेन से जबरन उतार दिए गए, जिसके बाद उन्हें पनवेल स्टेशन पर लगभग चार से पांच घंटे तक फंसा रहना पड़ा। यह घटना बंगलूरू में आयोजित ऑल इंडिया इंटर-यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप से लौटते समय हुई, जहां वे भोपाल के लिए सफर कर रहे थे। ट्रेन में तैनात टीटीई ने उनके पोल वॉल्ट पोल्स को अनधिकृत सामान बताते हुए आपत्ति जताई। यह पोल्स अत्यधिक महंगे, लगभग दो लाख रुपये प्रति पीस, पांच मीटर लंबे और खिलाड़ी के प्रदर्शन के लिए जरूरी होते हैं।

टीटीई को समझाने की कोशिश, अधिकारियों से बात करने की मांग और तत्काल जुर्माना चुकाने की पेशकश, लेकिन सबको खारिज कर दिया गया। आक्रोशित देव मीना ने वीडियो में कहा, 'हम यहां चार से पांच घंटे से बैठे हैं। अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो हमारे जूनियर्स के साथ क्या होगा? अगर एक इंटरनेशनल लेवल के एथलीट के साथ ऐसा भारत में हो सकता है, तो मैं क्या कहूं?' पोल वॉल्ट में उपयोग होने वाले पोल्स न तो किराये पर मिलते हैं और न ही आसानी से बदले जा सकते हैं। एक खिलाड़ी इन्हें अपने वजन, तकनीक और ऊंचाई के हिसाब से चुनता है, इसलिए यात्रा में इन्हें साथ ले जाना अनिवार्य होता है।

जुर्माना देकर मिली अनुमति, पर शर्तों के साथ

मीना ने कहा, 'सबको हमसे एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीद है, लेकिन अब तो खेल खत्म हो गया। हम यहीं बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोई हमारी मदद कर सके।' घंटों तक यह गतिरोध चलता रहा, जिसकी वजह से एथलीट्स अपनी कनेक्टिंग ट्रेन भी मिस कर गए। पोल वॉल्टर्स के लिए उनका उपकरण किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जा सकता। बैट या रैकेट के विपरीत, पोल एथलीट के वजन और जंप की ऊंचाई के अनुसार कस्टम बनाया जाता है। आखिरकार लंबे विवाद और जुर्माना भरने के बाद खिलाड़ियों को एक अन्य ट्रेन से जाने की अनुमति मिली, लेकिन शर्त यह रखी गई कि यदि किसी यात्री ने पोल्स के कारण शिकायत की, तो कार्रवाई की जाएगी।

टूर्नामेंट से नाम वापस लेंगे कैस्पर रूड! जैनिस त्जेन ने हासिल की बड़ी उपलब्धि

मेलबर्न, एजेंसी। इंडोनेशिया की युवा टेनिस खिलाड़ी जैनिस त्जेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में मंगलवार को एक ऐसा उपलब्धि हासिल किया, जिसका इंतज़ार 1998 से था। त्जेन ने कनाडा की 22वीं वरीयता प्राप्त लेला फर्नांडीज को सीधे सेटों में 6-2, 7-6(7/1) से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। 23 वर्षीय त्जेन इस जीत के साथ 28 साल बाद पहली इंडोनेशियाई खिलाड़ी बन गई, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में मुख्य ड्रॉ मैच जीता। इससे पहले यह उपलब्धि यायुक बासुकी ने 1998 में हासिल की थी।

यूक्रेन की ओलिन्यकोवा और साहस की कहानी

दूसरी ओर, यूक्रेन की ओलेक्सांद्रा ओलिन्यकोवा ने भले ही डिफेंडिंग चैंपियन मैडिसन कीज़ से 7-6(8/6), 6-1 से हार झेली, लेकिन उनका साहस पूरे एरेना को भावुक कर गया। 25 वर्षीय ओलिन्यकोवा ने कहा, 'यह मेरे करियर का सबसे अच्छा अनुभव है। इसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगी।' ओलिन्यकोवा ने यूएस ओपन से पहले अपनी ट्रेनिंग कीव में ही जारी रखी, जबकि शहर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों की चपेट में रहा। उन्होंने साझा किया, 'एक विस्फोट मेरे घर के पास हुआ। ड्रोन मेरे सामने वाली बिल्डिंग से टकराया। मेरा अपार्टमेंट धमाके से हिल रहा था।'उनके पिता यूक्रेनी सेना में तैनात हैं। हार के बाद भी वह मुस्कुराती रहीं और बोलीं, 'मुझे पता है कि यह उनका सपना था मुझे इस कोर्ट पर खेलने का। मैंने उनका सपना पूरा किया। अब मैं उन्हें और ज्यादा गर्व महसूस कराना चाहती हूं।' यह मैच सिर्फ टेनिस नहीं, बल्कि युद्धकाल में मानवीय दृढ़ता की कहानी था।

कैस्पर रूड टूर्नामेंट से हट सकते हैं

दूसरी ओर नॉर्वे के कैस्पर रूड ऑस्ट्रेलियन ओपन में दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं, लेकिन उनका मन पूरी तरह कोर्ट पर नहीं है। रूड जल्द ही पिता बनने वाले हैं और उनकी पत्नी मारिया किसी भी समय डिलीवरी पर जा सकती हैं। रूड ने कहा, 'मुझे मारिया का शुक्रिया करना होगा कि उन्होंने मुझे आने दिया। मेरे फोन की रिंगर हर समय ऑन रहती है। अगर वह लेबर में गईं, तो मैं अगले दिन यहां नहीं रहूंगा।'उन्होंने आगे जोड़ा, 'जिंदगी में सिर्फ टेनिस ही सब कुछ नहीं है। मैं यहां तब तक रहूंगा, जब तक मारिया चाहेंगी।' टेनिस में प्रोफेशनलिज्म और निजी जीवन के बीच संतुलन का यह एक मानवीय उदाहरण है। एक तरफ त्जेन ने इतिहास रचा, दूसरी तरफ ओलिन्यकोवा ने साहस दिखाया, और रूड ने साबित किया कि खिलाड़ी भी इंसान हैं।

न्यूज डायरी

सीसीआई द्वारा उद्योग विभाग, चण्डीगढ़ प्रशासन के सहयोग से आरएएमपी कार्यक्रम आयोजित

हिन्द जनपथ

चंडीगढ़ (ब्यूरो)। चैंबर ऑफ चण्डीगढ़ इंडस्ट्रीज (सीसीआई) द्वारा उद्योग विभाग, चण्डीगढ़ प्रशासन के सहयोग से आज कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई), सेक्टर 31 में रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉरमेंस (आरएएमपी) कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय सांसद मनीष तिवारी तथा एचएस लक्की, अध्यक्ष, चण्डीगढ़ कांग्रेस ने शिरकत की और उद्योग जगत के सदस्यों से संवाद किया। कार्यक्रम के दौरान संदीप साहनी ने वित्तीय साक्षरता पर, आकाश मित्तल ने व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (ओएचएस) तथा नए श्रम कानूनों पर तथा सोहम दासगुप्ता ने एमएसई-सीडीपी योजना पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इस सेमिनार की अध्यक्षता सुरिंदर गुप्ता, अध्यक्ष, सीसीआई ने की। उनके साथ नवीन मिगलानी, उपाध्यक्ष एवं अरुण गोयल, महासचिव भी मंचासीन रहे। सेमिनार में उद्योग जगत से जुड़े 115 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

72 घंटे में सुलझी 'शाहबाद मर्डर मिस्ट्री', मोहाली तक जुड़े तार

कुरुक्षेत्र/सोनीपत। रेलवे पटरियों को अपराध का सुरक्षित ठिकाना समझने वाले बदमाशों पर हरियाणा राजकीय रेलवे पुलिस ने करारा प्रहार किया है। महज तीन दिनों के भीतर जीआरपी ने एक ओर शाहबाद के सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाकर मुख्य आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाया, तो दूसरी ओर सोनीपत में यात्रियों के लिए सिरदर्द बने शातिर चोर को धर दबोचकर लाखों रुपये की संपत्ति बरामद की। यह कार्रवाई अपराधियों में खौफ और आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास को और मजबूत करती है।

अमल होटल के पास मिला था शव, जांच की कड़ी मोहाली तक पहुंची

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार मामला शाहबाद का है। 15 जनवरी 2026 को अमल होटल के समीप रेलवे लाइनों के किनारे सफेदों के झुंड में एक शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान राजेश चोपड़ा निवासी चंडीगढ़, हाल निवासी मोहाली के रूप में हुई, जिनकी गला रेतकर निर्मम हत्या की गई थी। शुरुआत में यह मामला पूरी तरह रहस्यमय था, लेकिन परिजनों ने राजेश के साथ काम करने वाले मोनू पर संदेह जताया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी रेलवे नितिका गहलोत के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई।

जयपुर से दिल्ली तक दबिश, अंबाला यार्ड से आरोपी गिरफ्तार

डीएसपी राजेश कुमार के नेतृत्व में इंस्पेक्टर संजय कुमार तथा टीम (एएसआई प्रदीप और कर्ण सिंह) ने मोहाली, पंचकूला, चंडीगढ़, दिल्ली और जयपुर तक व्यापक तलाशी अभियान चलाया। तकनीकी सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस ने मुख्य आरोपी मोनू उर्फ लुक्का (निवासी गोहाना, सोनीपत) को अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म यार्ड से गिरफ्तार कर लिया। 72 घंटे में हुई यह गिरफ्तारी जीआरपी की तेज और प्रभावी कार्यशैली का प्रमाण है। आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस को आशंका है कि इस वारदात में अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं।

चोरी का मोबाइल बेचने आया चोर, 4 बाइक और 8 मोबाइल बरामद

उधर, जीआरपी सोनीपत ने भी बड़ी सफलता हासिल की है। अक्टूबर माह की चोरी की घटनाओं की कड़ियां जोड़ते हुए जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम गश्त पर थी। गोहाना रोड ओवरब्रिज के पास चोरी का मोबाइल बेचने की सूचना पर एसआई धर्मपाल के नेतृत्व में एएसआई विकास कुमार ने दबिश दी और मुकेश कुमार उर्फ फुली (निवासी पलवल) को गिरफ्तार किया। आरोपी की निशानदेही पर करीब 4.10 लाख रुपये की संपत्ति बरामद हुई, जिसमें 4 मोटरसाइकिलें, 8 महंगे मोबाइल फोन, 2 ट्रॉली बैग और 1 पिट्ठू बैग शामिल हैं। इस कार्रवाई से रेलवे स्टेशनों पर चोरी व झपटमारी की घटनाओं पर लगाम लगने की उम्मीद है। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से और वारदातों के खुलासे की संभावना जताई जा रही है।

हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, पंचकूला द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में संस्कृत भाषण प्रतियोगिता एवं वैचारिक गोष्ठी का भव्य आयोजन

हिन्द जनपथ

पंचकूला (ब्यूरो)। हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, पंचकूला के संस्कृत प्रकोष्ठ द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में अकादमी भवन स्थित महाराजा दाहिर सेन सभागार में संस्कृत भाषण प्रतियोगिता एवं वैचारिक गोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में शिक्षा, संस्कृति और युवाओं की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सारगर्भित विचार प्रस्तुत किए गए।

कार्यक्रम में मुख्य वक्ताओं के रूप में प्रो. आर.के. देसवाल, डॉ. रामचंद्र, डॉ. आशुतोष अंगिरस तथा डॉ. जितेंद्र आर्य ने सहभागिता की। भाषण प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए महेश शर्मा को प्रथम, अतुल शर्मा को द्वितीय तथा वैभव शर्मा को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं मनदीप कौर को प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

अकादमी के कार्यकारी उपाध्यक्ष डॉ. कुलदीप चंद अग्निहोत्री ने अपने संबोधन में स्वामी विवेकानंद के आदर्शों से प्रेरित होकर कनेक्ट और कनेक्शन की अवधारणा को सरल शब्दों में समझाया और युवाओं को समाज के साथ सशक्त जुड़ाव स्थापित करने का आह्वान किया। अकादमी सदस्य सचिव श्री मनजीत सिंह ने भी युवाओं को आदर्श एवं दृढ़ संकल्पों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

प्रो. आर. के. देसवाल ने चरित्र निर्माण और भाषा पर सशक्त पकड़ को युवाओं की सफलता की कुंजी बताते हुए प्रेरक विचार रखे। डॉ. रामचंद्र ने विकसित भारत के परिप्रेक्ष्य में युवाओं की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि जीवन में ज्ञानार्जन के लिए भ्रमण अत्यंत आवश्यक है। डॉ. आशुतोष अंगिरस ने ऐसे आयोजनों की उपयोगिता रेखांकित करते हुए कहा कि इनसे हमें कुछ सीखकर और साथ लेकर जाना चाहिए। डॉ. जितेंद्र आर्य ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि स्थानों की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही जीवंत है, क्योंकि यहां से विद्यार्थियों को मूल्यवान संदेश प्राप्त होते हैं। डॉ. राजबीर तथा आचार्य कपिल ने भी इस अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत किये।

राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल पंचकूला में, मुख्यमंत्री गुरुग्राम में फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज

लोक भवन चंडीगढ़ में होगा 'एट होम' कार्यक्रम

हिन्द जनपथ

चंडीगढ़ (ब्यूरो)। हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष 26 जनवरी को राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में पंचकूला तथा मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। 'एट होम' कार्यक्रम लोक भवन, चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। राज्य के सभी मंडलों, जिलों, उपमंडलों, तहसीलों और अन्य प्रमुख स्थानों पर प्रातः 10.00 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा।

मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा इस आशय का एक पत्र जारी किया गया है।

अम्बाला में सांसद श्रीमती रेखा शर्मा, भिवानी में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा, चरखी दादरी में सांसद श्री धर्मबीर सिंह, फरीदाबाद में स्वास्थ्य मंत्री सुश्री आरती सिंह राव, फतेहाबाद में हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष श्री कृष्ण लाल मिड्ढा, नवगठित जिला हांसी में केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामले तथा ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल, हिसार में स्कूल शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा, झज्जर में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री श्री राजेश नागर,

जींद में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती श्रुति चैधरी और कैथल में सांसद श्री नवीन जिंदल ध्वजारोहण करेंगे।

करनाल में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंद्र कल्याण, कुरुक्षेत्र में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी, महेंद्रगढ़ में उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह, नूंह में सांसद श्री सुभाष बराला, पलवल में सांसद श्री रामचंद्र जांगड़ा, पानीपत में विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार, रेवाड़ी में युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम, रोहतक में सहकारिता मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा, सिरसा में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री विपुल गोयल, सोनीपत में कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा तथा यमुनानगर में ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे।

जिला अम्बाला के नारायणगढ़ में मंडल आयुक्त, बराड़ा में उपमंडल अधिकारी (नागरिक), लोहारू में बवानी खेड़ा के विधायक श्री कपूर सिंह, तोशाम में जिला परिषद, चरखी दादरी के चेयरमैन श्री मनदीप डालावास, सिवानी में भिवानी के विधायक श्री घनश्याम सर्राफ, बाढड़ा में स्थानीय विधायक श्री उमेद सिंह गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे।

बड़खल में स्थानीय विधायक श्री धनेश अदलखा, बल्लभगढ़ में स्थानीय विधायक श्री मूलचंद शर्मा, टोहाना में नलवा के विधायक श्री रणधीर पनिहार, रतिया में जिला परिषद, फतेहाबाद की अध्यक्ष श्रीमती सुमन खीचड़, पटौदी में स्थानीय विधायक श्रीमती बिमला चैधरी, बादशाहपुर में रेवाड़ी के विधायक श्री लक्ष्मण सिंह यादव, मानेसर में गुरुग्राम के विधायक श्री मुकेश शर्मा, सोहना में स्थानीय विधायक श्री तेजपाल तंवर, नारनौंद में हांसी के विधायक श्री विनोद भ्याणा, बरवाला में हिसार की विधायक श्रीमती सावित्री जिंदल, बहादुरगढ़ में स्थानीय विधायक श्री राजेश जून, बादली में जिला परिषद झज्जर के अध्यक्ष श्री कप्तान सिंह, बेरी में चरखी दादरी के विधायक श्री सुनील सतपाल सांगवान, जुलाना में जिला परिषद जींद की अध्यक्ष श्रीमती मनीषा रानी, सफीदों में स्थानीय विधायक श्री रामकुमार गौतम, उचाना कलां में स्थानीय विधायक श्री देवेंद्र चतरभुज अत्री और नरवाना में पानीपत शहर के विधायक श्री प्रमोद कुमार ध्वजारोहण करेंगे।

जिला कैथल के गुहला में पुंडरी के विधायक श्री सतपाल जांबा, कलायत में जिला परिषद कैथल के अध्यक्ष श्री कर्मबीर कौल, नीलोखेड़ी में स्थानीय विधायक श्री भगवान दास, इंद्री में स्थानीय विधायक श्री रामकुमार कश्यप, घरौंडा में करनाल के विधायक श्री जगमोहन आनंद, असंध में स्थानीय विधायक श्री योगेंद्र सिंह राणा, लाडवा में मंडलायुक्त, शाहाबाद में जिला परिषद कुरुक्षेत्र की अध्यक्ष श्रीमती कंवलजीत कौर, पेहोवा में करनाल की मेयर श्रीमती रेणू बाला गुप्ता, महेन्द्रगढ़ में नारनौल के विधायक श्री ओम प्रकाश यादव, कनीना में महेन्द्रगढ़ के विधायक श्री कंवर सिंह, नांगल चैधरी में फरीदाबाद एनआईटी के विधायक श्री सतीश फागना, फिरोजपुर झिरका में जिला परिषद नूह के अध्यक्ष श्री जान मोहम्मद, तावडू में फरीदाबाद के मेयर श्री प्रवीण जोशी, पुन्हाना में गुरुग्राम की मेयर श्रीमती राज रानी, हथीन में जिला परिषद पलवल की अध्यक्ष श्रीमती रेखा, होडल में स्थानीय विधायक श्री हरेन्द्र सिंह, कालका में स्थानीय विधायक श्रीमती शक्ति रानी शर्मा, इसराना में समालखा के विधायक श्री मनमोहन भडाना और समालखा में राई की विधायक श्रीमती कृष्णा गहलावत ध्वजारोहण करेंगी।

बावल में स्थानीय विधायक डॉ. कृष्ण कुमार, कोसली में स्थानीय विधायक श्री अनिल यादव, महम में रोहतक के मेयर श्री राम अवतार वाल्मीकि, सांपला में जिला परिषद रोहतक की अध्यक्ष श्रीमती मंजू हुड्डा, कालांवाली में जिला परिषद हिसार के अध्यक्ष श्री सोनू सिहाग, डबवाली में उपमंडल अधिकारी (नागरिक), ऐलनाबाद में हिसार के मेयर श्री प्रवीन पोपली, गन्नौर में स्थानीय विधायक श्री देवेंद्र कादियान, खरखौदा में स्थानीय विधायक श्री पवन खरखौदा, गोहाना में सोनीपत के विधायक श्री निखिल मदान, व्यासपुर में यमुनानगर के विधायक श्री घनश्याम दास अरोड़ा, छछरौली में यमुनानगर की मेयर श्रीमती सुमन बहमनी और रादौर में जिला परिषद यमुनानगर के अध्यक्ष रमेश चंद राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे।

नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से देश के युवाओं में नई ऊर्जा का संचार — कुलभूषण गोयल

हिन्द जनपथ

पंचकूला (ब्यूरो)। भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व के अंतर्गत नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर पंचकूला के पूर्व मेयर कुलभूषण गोयल ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। कुलभूषण गोयल ने कहा कि नितिन नबीन जैसे युवा, कर्मठ और ऊर्जावान नेता का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना न केवल पार्टी के लिए बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के लिए भी गर्व का विषय है। इससे युवाओं को राजनीति में सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व के लिए प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा को युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने से संगठन में नई सोच, नई दिशा और नई गति देखने को मिलेगी। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवा सशक्तिकरण के संकल्प को और मजबूत करता है। पूर्व मेयर कुलभूषण गोयल ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष पं. मोहन लाल कौशिक सहित वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में भाजपा संगठन बूथ स्तर तक और अधिक सशक्त होगा। उन्होंने कहा कि पंचकूला जिला संगठन भी पूरी निष्ठा, समर्पण और उत्साह के साथ पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने और संगठन विस्तार के लिए कार्य करता रहेगा।

हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग द्वारा सामुदायिक केंद्र सेक्टर-12 में सफाई कर्मचारियों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन

- लगभग 300 सफाई कर्मचारी और उनके परिजनों ने करवाई निशुल्क जांच
- आयोग चेयरमैन ई. कृष्ण कुमार ने किया सफाई मित्रों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक
- प्रदेश को साफ सुथरा रखने में सफाई कर्मचारियों का अहम योगदान-वाईस चेयरमैन

हिन्द जनपथ

पंचकूला (ब्यूरो)। हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, जिला प्रशासन व नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में पंचकूला के सफाई कर्मचारियों के लिए आयोग के चेयरमैन श्री कृष्ण कुमार के मार्गदर्शन में 19 जनवरी से 21 जनवरी, 2026 तक तीन दिवसीय जिला स्तरीय स्वास्थ्य जाँच शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

इस उपलक्ष्य में सामुदायिक केंद्र सेक्टर-12 पंचकूला में आज स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 300 सफाई कर्मचारियों व उनके परिवारों की निशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई।

इस मौके पर हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन ई. कृष्ण कुमार ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की और जांच शिविर में आए सफाई कर्मचारियों से बातचीत भी की।

श्री कृष्ण कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छ जीवन ही मनुष्य सबसे बडी पूंजी है। उन्होंने कहा कि अच्छा स्वास्थ्य होगा तभी सफाई कर्मचारी अच्छे से अपना कार्य कर पाएंगे और शहर को स्वच्छ, सुंदर रखने में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए प्रदेशभर में जांच शिविर लगाए जा रहे है ताकि स्वास्थ्य कर्मी स्वस्थ व तंदुरूस्त रह सके।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत का संदेश दिया है। उन्होंने स्वयं सफाई मित्रों के चरण धोकर इस अभियान को आगे बढाया। आयोग के चेयरमैन श्री कृष्ण कुमार ने जिलावासियों से भी आह्वान किया कि वे गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग कूडेदान में डाले ताकि सफाई कर्मचारी बेहतर और व्यवस्थित तरीके से कचरे का निष्पादन कर सके।

उन्होंने कहा कि सफाई मित्रों को अपने कार्य के साथ साथ अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति भी सजग रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सफाई मित्र कार्य के दौरान मास्क और दस्ताने पहनने। यदि सफाई मित्रों को किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है तो अपनी जांच अवश्य करवाए। आयोग द्वारा भी प्रदेशभर में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जहां कोई भी सफाई कर्मचारी अपनी व अपने परिवार की निशुल्क स्वास्थ्य जांच करवा सकता है। उन्होनें सफाई कर्मियों से अपने व अपने परिवार की स्वास्थ्य की निशुल्क जांच का लाभ उठाने की अपील की।

हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के वाइस चेयरमैन आजाद सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य जांच सफाई मित्रों के लिए बहुत जरूरी है। इससे उन्हें अपने शरीर में आ रहे विकार का पता लग जाता है और वे समय रहते अपना इलाज करवा सकते है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को साफ व सुथरा रखने मे सफाई कर्मी अपना अहम रोल निभाते है। हरियाणा सरकार भी उनके हित में बढचढकर कार्य कर रही है। आयोग की कोऑर्डिनेटर नीलम और रोहिना ने शिविर की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 19 से 21 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान के तहत जिले के सभी सीएचसी (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र), पीएचसी (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) और पॉलीक्लिनिक में जाँच की जा रही है।

आरआईसीएम, चंडीगढ़ में भारत–श्रीलंका सहकारी संवाद : व्यापार एवं क्षमता निर्माण पर आयोजन

हिन्द जनपथ

चंडीगढ़ (ब्यूरो)। क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (आरआईसीएम), चंडीगढ़ द्वारा उन्नती एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी, होशियारपुर (पंजाब) के सहयोग से दिनांक 20 जनवरी 2026 को आरआईसीएम परिसर में भारत–श्रीलंका सहकारी संवाद : व्यापार एवं क्षमता निर्माण का आयोजन किया गया। यह संवाद डॉ. शंथा जयारथने, वरिष्ठ परामर्शदाता, व्यापार, वाणिज्य, खाद्य सुरक्षा एवं सहकारी विकास मंत्रालय तथा माननीय सहकारिता मंत्री, श्रीलंका सरकार के सलाहकार एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास संस्थान, श्रीलंका के निदेशक, की भारत यात्रा के संदर्भ में आयोजित किया गया। इस अवसर पर भारत के चयनित सहकारी नेताओं, सहकारी संस्थानों के प्रतिनिधियों तथा विकास क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने भाग लिया।

कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 10:00 बजे हुआ, जबकि सम्मेलन सत्र 11:00 बजे प्रारंभ हुआ। इस संवाद का उद्देश्य भारत और श्रीलंका के बीच सहकारी-से-सहकारी सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए, विशेषकर व्यापार, संस्थागत साझेदारी एवं क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में, विचार-विमर्श एवं अनुभव साझा करने हेतु एक केंद्रित मंच प्रदान करना था।

प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए आरआईसीएम के निदेशक डॉ. राजीव कुमार ने दोनों देशों के सहकारी आंदोलनों के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं संस्थागत संबंधों पर प्रकाश डाला तथा साझा मूल्यों को व्यावहारिक सहयोग में रूपांतरित करने हेतु संरचित सहभागिता की आवश्यकता पर बल दिया। अपने संबोधन में डॉ. शंथा जयारथने ने श्रीलंका के सहकारी पारितंत्र, नीतिगत दृष्टिकोण एवं द्विपक्षीय सहयोग की उभरती संभावनाओं पर अपने विचार साझा किए।

संवाद के प्रमुख विषयों में कृषि, मूल्यवर्धित उत्पादों, मत्स्य पालन एवं सेवाओं में सहकारी-नेतृत्व वाले व्यापार की संभावनाएँ; प्रशिक्षण, नेतृत्व विकास एवं अध्ययन-भ्रमण से संबंधित संयुक्त पहलें; तथा दोनों देशों के सहकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों के बीच संस्थागत सहयोग शामिल रहे।

संवाद का समापन दो से तीन ठोस सहयोगात्मक मार्गों की पहचान, संभावित पायलट पहलों की खोज तथा संस्थागत समझौता ज्ञापनों (MoUs) एवं विनिमय कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने पर सहमति के साथ हुआ। यह कार्यक्रम भारत और श्रीलंका के सहकारी क्षेत्रों के बीच सतत एवं पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुआ।

बजट-पूर्व परामर्श कार्यक्रम: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज मानेसर और पानीपत में विभिन्न हितधारकों से करेंगे संवाद

हिन्द जनपथ

चंडीगढ़ (ब्यूरो)। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी आज मानेसर एवं पानीपत में आयोजित बजट-पूर्व परामर्श कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आगामी राज्य बजट को अधिक समावेशी, विकासोन्मुख और जनआकांक्षाओं के अनुरूप तैयार करना है। राज्य सरकार द्वारा बजट निर्माण की प्रक्रिया में समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

मानेसर एवं पानीपत में होने वाली इस बैठक में राज्य सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, उद्योगपति, औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि, व्यापार जगत से जुड़े प्रमुख हितधारक तथा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ उपस्थित रहेंगे। बैठक के दौरान औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन, रोजगार सृजन, आधारभूत ढांचे के विस्तार, कौशल विकास, नवाचार तथा राज्य की आर्थिक प्रगति से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इस बजट-पूर्व परामर्श कार्यक्रम के माध्यम से सरकार का प्रयास है कि नीति निर्माण में सुझावों को सम्मिलित किया जाए, ताकि आगामी बजट प्रदेश के समग्र विकास को नई दिशा दे सके और हर वर्ग को समान अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी इससे पूर्व फरीदाबाद, गुरुग्राम एवं हिसार में आयोजित बजट-पूर्व परामर्श कार्यक्रमों में भी भाग ले चुके हैं। इन बैठकों के दौरान महिलाओं, पंचायत प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों तथा समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया था। इन संवादों के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों और विकास से जुड़े सुझावों को संकलित किया गया। राज्य सरकार द्वारा आयोजित ये बजट-पूर्व परामर्श कार्यक्रम आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक मजबूत, संतुलित और भविष्य उन्मुख बजट तैयार करने की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं, जिसमें विकास, सामाजिक न्याय और आर्थिक सुदृढ़ता के बीच संतुलन स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उपायुक्त ने जिला के सभी नशा मुक्ति और काउंसलिंग-सह-पुनर्वास केंद्रों की आयोजित बैठक की करी अध्यक्षता

हिन्द जनपथ

पंचकूला (ब्यूरो)। उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने लघु सचिवालय के सभागार में जिला के सभी नशा मुक्ति और काउंसलिंग-सह-पुनर्वास केंद्रों की आयोजित बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. विशाल सैनी ने उपायुक्त को जिले में चल रहे नशा मुक्ति और काउंसलिंग-सह-पुनर्वास केंद्रों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला में कुल 5 नशा मुक्ति केंद्र और 7 काउंसलिंग-सह-पुनर्वास केंद्र हैं। उपायुक्त ने सिविल अस्पताल पंचकूला के स्टाफ की संख्या के बारे में जानकारी मांगी और निर्देश दिए कि इसे हरियाणा ड्रग अबूस मॉनिटरिंग सिस्टम (एच-डीएएमएस) पोर्टल पर भी अपडेट किया जाए। इस संबंध में उप-सिविल-सर्जन डॉ. संदीप जैन ने उपायुक्त को मौजूदा स्टाफ की संख्या के बारे में अवगत करवाया और आश्वासन दिया कि विवरण जल्द से जल्द एचडीएएमएस पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाएगा। उपायुक्त ने सभी नशा मुक्ति और काउंसलिंग-सह-पुनर्वास केंद्रों को निर्देश दिया कि वे अपने रिकॉर्ड को अपडेट रखें और एचडीएएमएस पोर्टल पर अपलोड करें। उन्होंने मरीजों के इलाज, लंबित केस शीट की स्थिति, दैनिक ओ.पी.डी. में आने वाले मरीजों की संख्या और केंद्रों द्वारा प्रत्येक मरीज को दिए गए समय की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी केंद्रों को अगली बैठक में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें इलाज किए जा रहे मरीजों के प्रकार और प्रत्येक मरीज को दी गई काउंसलिंग/थेरेपी की अवधि का उल्लेख हो। इसके अलावा उपायुक्त ने सदस्य सचिव को सभी केन्द्रों का निर्धारित मानदंडों के अनुसार नियमित रूप से तिमाही निरीक्षण और औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया।